घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 251- रविवार 12- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत-न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित 18 फैसले हुए....

मैं 25 साल पुराना मफलर पहनकर न्यूजीलैंड आया,यहीं मुझे गिफ्ट मिला था : पीएम मोदी

ऑकलैंड,11 जुलाई 2026। पीएम मोदी ने शनिवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने करीब तीन दशक पुराना किस्सा सुनाया। पीएम ने कहा...25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था,तब मुझे यहां आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दीं,जो मैं भारत लेकर गया। एक-मफलर, दूसरी-कैप और तीसरा-एक सेट दस्ताना। उसमें भी एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। इस मफलर को मैंने कई बार इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। पीएम ने आगे कहा कि हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं,जनकल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद मोदी भारत के लिए रवान हो गए। इससे पहले मोदी ने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 समझौतों पर साइन किए गए। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35 हजार करोड़ करने का लक्ष्य रखा। पीएम मोदी ने कहा...भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं,अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है।

मोदी बोले...कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में बात करें तो ये कोलेब का जमाना है....

मोदी ने कहा- अगर हम कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में बात करें तो ये कोलेब का जमाना है। दोनों देश स्पोर्ट्स में भी बहुत शानदार कोलेब कर सकते हैं। रग्बी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। हमें कोच चाहिए,एक्सपर्ट चाहिए। न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य जुड़ा है। स्पेस से सेक्टर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ पोल पर लैंड किया तो न्यूजीलैंड नाच रहा था। उस दिन हमें गर्व हुआ। यहां की स्पेस कंपनियों ने कई बार हमारे साथ मिलकर काम किया है। स्पेस सेक्टर बताने कि लिए काफी है कि दोनों देश एक दूसरे को कितना कुछ दे सकते हैं।

मोदी बोले...भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल दे रहा है...

पीएम ने कहा...भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल दे रहा है। यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकॉनोमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत जितना फोकस इकॉलोजी और इकॉनोमी पर देता है उतना ही हैरिटेज पर भी देता है। हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा साहसा और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर कोने में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है।

दूरी हजारों किमी,मगर दिल में हिंदुस्तान बसता है : प्रवासियों भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा...हजारों किमी दूर रहते हुए भी आपके दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं हिंदुस्तान बसता ही है। शरीर यहां होगा मन भारत में होगा। इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं। जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर देखते हैं तो बहुत कुछ चीजें छूट जाती हैं लेकिन टीवी पर देखने से हर बारीकी का पता चलता है। वैसे ही आपको भारत की हर बारीकी का पता चलता है।

मोदी बोले...हमने न्यूजीलैंड से बहुत कुछ सीखा है...

आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहेजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में,हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। इसका कारण है सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जनकल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। यह वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। आज हम देखते हैं कि यहां की सोसायटी में महिलाएं बहुत बड़े पैमाने पर योगदान दे रही है। भारत भी महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। रूरल इकॉनोमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। इसकी ताकत एग्रीकल्चर के इर्द-गिर्द बनाया गया। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर देश के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने दिखाया है कि छोटे बाजार भी बड़े ब्रांड बन सकते हैं।

मोदी बोले...मैं 25 साल पहले भी न्यूजीलैंड आया था...

पीएम मोदी ने कहा...भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए,आप सभी लोगों के लिए,140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। पीएम के रूप में मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार का हिस्सा नहीं था,तब मुझे यहां आने का मौका मिला था। उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दीं,जो मैं भारत लेकर गया। एक- ये मफलर, एक कैप और एक सेट दस्ताना। ठंड का मौसम था, और उसमें भी एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया और आज भी संभाल कर रखा है। जैसे आपके प्यार को संभालकर रखता हूं।

न्यूजीलैंड पीएम बोले...भारत कितना एनर्जेटिक है,यहां दिखता है...

न्यूजीलैंड पीएम ने कहा... कई सालों तक लोग कहते थे कि दोनों देशों के बीच एफटीए नहीं हो सकता। लेकिन मैंने और पीएम मोदी ने यह करके दिखाया। हमें भारतीयों की उर्जा देखने के लिए दिल्ली-मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। वह एनर्जी आज यहीं पर है। मैंने देखा है कि भारतीय कितनी मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। एक साथ दो-दो, तीन-तीन नौकरियां करते हैं।

पर्यटकों की नाव वियतनाम में डूबी...

15 भारतीय लोगों की मौत

नई दिल्ली,11 जुलाई 2026। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार को बोट पलट गई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक,इनमें से 32 भारतीय थे। 15 भारतीयों की मौत हो गई। ज्यादातर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पर्यटक थे। बोट पर कुल 4 क्रू मेंबर्स समेत 36 लोग सवार थे। 21 लोगों को बचा लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा सुबह 10:30 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे की वजह समुद्र की ऊंची लहरें हो सकती हैं। जो वीडियो सामने आए, उनमें लहरें उठती दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। नाव जब पलटी तो टूरिस्ट नाव के नीचे फंस गए।

फु क्वोक द्वीप से रवाना हुई नाव : बोट भारतीय पर्यटकों को फु क्वोक द्वीप के पास स्थित 'होन मे रुट' से न्गोआई द्वीप घुमाने ले जा रही थी, लेकिन यह तट से लगभग 400 मीटर पहले ही पलट गई। न्गोआई द्वीप अपने साफ समुद्र, छोटे बीच और कोरल रीफ डाइविंग के लिए मशहूर है। यहां पहुंचने के लिए पर्यटक आमतौर पर एन थोई बंदरगाह से बोट या स्पीडबोट किराये पर लेते हैं।

32 भारतीयों में 2 महिलाएं भी बोट में सवार थी : वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बोट में सवार भारतीयों के नाम जारी किए हैं। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। 32 भारतीयों के नाम देखें- बालासुब्रमणि पलानीसामी, सेल्वम पिचियाह, सेंथिल

कुमार जयवेल,शिवकुमार मुथुकुमारसामी,निर्मल कुमार सेथुरामन,मुरुगा प्रभु अरुमुगम,रुबन सेल्वा नाथन जैकब येसुपथम,श्रीधर धर्मराजन, विग्नेश्वर राधाकृष्णन गोपाल,रामासुब्बु अन्नावी,अबुथल्खा जहीरुद्दीन,श्रीधर सुन्दरराजन,वाम्शीदर सेल्लूर रामराज,सेंजादैवेल कुप्पुसामी,नागलामडुगु सोहन, नल्लापेटा आदिशेशैया रवितेजा, शेख अब्दुल्लाह अब्दुल मजीद,राजीव कलैवानन,बालाजी नटेसन, विनया कुमार चितापुरम भास्कर, रविशंकर सुगुमारन, विपुल उत्तम चंद, संतोष कुमार शांतिलाल जैन,बाबू कुप्पुस्वामी,अलागुराजन शिवसामी, वसंता कुमार आनंदहन, श्रीधर मुदियम, किशोर गेल्ली, एविकॉट चेरियन थॉमस, रमेश कुमार पचियप्पन, लोवेनी थॉमस, जया लक्ष्मी गेल्ली।

भारतीय नौसेना की बढ़ी ताकत,मिला नया ताकतवर युद्धपोत 'महेंद्रगिरि'

रक्षा मंत्री बोले...यह देश की सुरक्षा में मील का पत्थर

नई दिल्ली,11 जुलाई 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरि को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया। यह प्रोजेक्ट-17ए के तहत निर्मित छठा स्वदेशी युद्धपोत है, जिसे भारतीय नौसेना के ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश देश के रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण क्षेत्र में एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने बताया कि आईएनएस महेंद्रगिरि हवा, समुद्र और पानी के भीतर से आने वाले खतरों का एक साथ मुकाबला करने में सक्षम है। नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित समारोह में वरिष्ठ नौसेना अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के वैश्विक घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि किसी भी देश के लिए एक सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली नौसेना कितनी आवश्यक होती है। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय नौसेना ने 'ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा' के तहत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का आवश्यक सामान लेकर जा रहे 18 व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय नौसेना केवल एक मजबूत सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक हितों की भी प्रभावी संरक्षक है। आईएनएस महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है, जबकि इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (मुंबई) ने किया है। यह भारत की सबसे आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें दुश्मन के रडार से बचने की उन्नत तकनीक, अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली और उच्च स्तर का ऑटोमेशन शामिल है। यह युद्धपोत समुद्र में विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। इस युद्धपोत में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की सफलता को दर्शाता है। इसके निर्माण में देश की अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिला है। महेंद्रगिरि में स्वदेशी हथियार,आधुनिक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस किया गया है। यह हवा, समुद्र की सतह और पानी के भीतर मौजूद दुश्मन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। इसके अलावा यह समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव अभियान, आपदा राहत और मानवीय सहायता जैसे अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसकी लंबी समुद्री तैनाती क्षमता इसे हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भी प्रभावी संचालन में सक्षम बनाती है। इस युद्धपोत का नाम पूर्वी घाट की महेंद्रगिरि पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह भारतीय नौसेना का पहला जहाज है जिसे यह नाम दिया गया है। यह नाम शक्ति,दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। अधिकारियों के अनुसार,आईएनएस महेंद्रगिरि के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सीबीएसई का बड़ा फैसला...7वीं से 9वीं के विद्यार्थियों को मिली राहत

10वीं में थर्ड लैंग्वेज एग्जाम से छूट

नई दिल्ली,11 जुलाई 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपनी त्रिभाषा नीति को लेकर नई दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी हो रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिसमें से कम से कम दो भाषाओं का भारतीय होना अनिवार्य है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। साथ ही, बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे छात्रों के कक्षा स्तर के अनुरूप ही शिक्षण सामग्री सुनिश्चित करें।

त्रिभाषा नीति का क्रियान्वयन और चयन प्रक्रिया

नई नीति के अनुसार, कक्षा नौ के छात्रों को तीन भाषाओं का चयन करना होगा। इसमें उन्हें हिंदी,संस्कृत,तमिल,तेलुगु,बंगाली,मराठी,गुजराती, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं में से किन्हीं दो का चुनाव करना होगा, जबकि तीसरी भाषा के रूप में वे अंग्रेजी,फ्रेंच,जर्मन या स्पेनिश जैसी किसी अन्य भाषा को चुन सकते हैं। यदि कोई छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहा है, तो वह तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा का विकल्प ले सकता है। वहीं, जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हुई हैं, उन्हें सत्र 2026-27 के लिए विशेष छूट दी गई है, लेकिन उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा को जोड़ना अनिवार्य होगा।

आंतरिक मूल्यांकन और बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि कक्षा नौ के विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा का मूल्यांकन पूरी तरह से आंतरिक स्तर पर,जैसे कि असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। जब यही बैच वर्ष 2027-28 में कक्षा 10 में पहुंचेगा,तब भी तीसरी भाषा की कोई बोर्ड परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषा समझ का विस्तार करना और उन्हें विविध भाषाओं में निपुण बनाना है। वर्तमान में जो छात्र कक्षा सात और आठ में हैं,वे जब आगामी वर्षों में माध्यमिक स्तर पर पहुंचेंगे,तो उन्हें भी इसी त्रिभाषा संरचना का पालन करना होगा

नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर दतिया में बवाल...एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल

प्रदर्शकारियों ने हाइवे पर किया पथराव-चक्काजाम,जिले में धारा 163 लागू

भोपाल,11 जुलाई 2026। मध्यप्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जिला सुलग उठा है। टिकट बदलने से नाराज समर्थकों का विरोध शनिवार तड़के बेहद उग्र हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। दरअसल, दतिया विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था और लगातार जनसभाएं कर रहे थे। हालांकि, पार्टी ने आखिरी वक्त पर आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी। दतिया सीट के लिए अब तक 13 लोग फॉर्म खरीद चुके हैं, जिनमें से 4 ने नामांकन दाखिल भी कर दिया है।

भाजपा द्वारा टिकट की घोषणा होते ही पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ गई। डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने शुक्रवार को ग्वालियर-झांसी हाईवे समेत जिले के कई स्थानों पर चक्काजाम कर दिया गया। शुक्रवार शाम से शुरू हुआ असंतोष शनिवार सुबह तड़के करीब 4:30 बजे हिंसक झड़प में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर-झांसी हाईवे पर करीब 15 से 20 किलोमीटर लंबा चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और एक गाड़ी को पलट दिया गया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस पथराव में दतिया एसपी, एसडीओपी समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा के भी कुछ समर्थकों के चोटिल होने की खबर है। बड़ौनकलां में चक्काजाम की खबर के बाद प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए दतिया स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। दफ्तर के अंदर मौजूद करीब 250 कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के लिहाज से अंदर ही रोक दिया गया। कुछ समर्थकों ने खुद को अंदर बंद भी कर लिया था, जिन्हें बाद में अफसरों की समझाइश पर बाहर निकाला गया।

चढ़ावे की गिनती में बड़ा बदलाव

अब एक ही शिफ्ट में होगी गणना

अयोध्या,11 जुलाई 2026। अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर में हाल ही में सामने आई चढ़ावा चोरी की घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस घटना के बाद मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आमूल-चूल परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। अब मंदिर परिसर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के समय में बदलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत,अब चढ़ावे की गिनती के लिए केवल एक ही निर्धारित शिफ्ट होगी,जो सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए नई समय-सीमा

ट्रस्ट के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य दान-पात्रों और चढ़ावे के प्रबंधन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। अब तक चढ़ावा विभिन्न समयों पर या अलग-अलग पालियों में गिना जाता था,जिससे प्रबंधन में विसंगतियों की आशंका बनी रहती थी। एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने से न केवल कर्मचारियों पर निगरानी रखना आसान होगा,बल्कि संपूर्ण प्रक्रिया को सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी में एक साथ पूरा किया जा सकेगा। यह बदलाव मंदिर प्रबंधन की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिसके तहत भगवान राम के भक्तों द्वारा दिए गए दान की पाई-पाई का हिसाब रखने और उसे पूरी सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया गया है।

मंदिर प्रशासन का कड़ा रुख: अनुशासन सर्वोपरि

चढ़ावा चोरी के मामले ने मंदिर प्रशासन को भी आत्मचिंतन पर मजबूर किया है। इस अप्रिय घटना के बाद,ट्रस्ट के पदाधिकारी निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के साथ मिलकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाए
गा। दान प्रबंधन में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है,ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस नई व्यवस्था में डिजिटल ट्रैकिंग और सख्त भौतिक निगरानी को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

न्याय : बच्चे को पटक-पटक कर मारने वाले नर पिशाच को 41 दिन में फांसी की सजा..

कोर्ट ने कहा...वारदात बेहद जघन्य.. बीच सड़क 27 बार पटका था मासूम को

नई दिल्ली,11 जुलाई 2026। डेढ़ साल के मासूम की सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने वाले आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को अदालत ने शुक्रवार को मात्र 41 दिन में फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने हत्या के दोषी विराज को दोषी करार देने के बाद कड़ी सजा दी और उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

घटना 30 मई की है, जब बदायूं के सिविल लाइंस निवासी विराज ने रिश्ते की भाभी के शादी के प्रस्ताव ठुकराने पर गुस्से में आकर डेढ़ साल के भतीजे आरव को घर से लगभग 50 मीटर दूर सुनसान पक्की सड़क पर पटक-पटक कर मार डाला। वारदात का दिल दहला देने वाला भयावह दृश्य पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था, जो अभियोजन के अनुसार मुकदमे का सबसे निर्णायक साक्ष्य रहा। अदालत ने कहा कि वारदात बेहद जघन्य थी और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य व गवाहियों से दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपित ने सेकंडों में लगातार 8 बार और कुल 27 बार मासूम की बेरहमी से पटककर हत्या की यह कृत्य समाज के लिए चिंताजनक और असहनीय है।

संपादकीय

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल

यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि ई-20 ईंधन अर्थात एथनाल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज भले ही कुछ कम होता हो,लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक है।

और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता,क्योंकि एक अर्से से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही थीं कि 20 प्रतिशत एथनाल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी-खासी कमी आने के साथ ही वाहन के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे फर्जी वीडियो शेयर किए कि ई-20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई।

इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही,यह काम किया गया,लेकिन अभी इस बारे में स्पष्टता की अपेक्षा है कि क्या पांच-छह साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी ई-20 पेट्रोल उपयुक्त है? उचित यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही आटो कंपनियां भी आगे आएं।

यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में आटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर आटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है।

ई-20 मामले से सरकार को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों को भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्यों से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लाबी की ओर से ई-20 ईंधन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। नीति-नियंताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए।

यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि ई-20 ईंधन से माइलेज में महज 3-4 प्रतिशत की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता तो शायद एथनाल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। आखिर इसके पहले ई-10 पेट्रोल का उपयोग हो ही रहा था और उसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं थी।

इस तथ्य की भी अनदेखी न की जाए कि विश्व के कई देशों में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनाल मिलाया जाता है। ब्राजील तो बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक लीडर है। यहां सामान्य पेट्रोल में 27 से 30 प्रतिशत तक एथनाल मिलाया जाता है।

गिफ्ट देखकर नहीं बल्कि दिल से दोस्ती निभाओ

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर, बिहार

आज-कल रिश्ते दिल से नहीं बल्कि मतलब से निभाए जाते हैं - ये बात एक बार फिर समझ आ गई मुझे,जब एक घटना सुनी । सुनकर मानो मैं रुक गई,थम गई क्योंकि आज की इस आधुनिक दुनिया में इंसान की कीमत उसके जज़्बात से नहीं,उसकी जेब से लगाई जाती है। इधर मैं हर रोज देख रही हूँ कि लोगों को आज-कल लोगों से ज़्यादा वस्तुओं की चिंता हो गई है। किसी के लिए आप तन,मन,धन से सब कुछ कर दे,तो उसकी कोई कद्र नहीं। आप रात-रात भर जागकर उसकी बीमारी में सेवा करो,उसके सुख-दुख में खड़े रहो,तो आप नॉर्मल हो। वही आप बाजार से महँगा सा गिफ्ट खरीद कर दे दो,तो आप अचानक बहुत अच्छे हो गए मतलब आज के समय में आपके जज़्बात की कोई कीमत नहीं,पर आपके पैसे से खरीदे गए तोहफे की कीमत है। इस घटना से यही समझ में आया कि इस आधुनिक दुनिया में लोग सिर्फ पैसे और वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि आप उनका सम्मान कितना करते हैं। उनको बस फर्क पड़ता है कि हमको कितने का क्या मिलता है। दोस्ती, यारी और रिश्तों का मीटर अब प्यार से नहीं, बल्कि प्राइस टैग से चलता है-ये तो समझ गई मैं। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इस दुनिया में सबसे अच्छे हो,अगर नहीं हैं तो सबसे खराब और सबसे खूबसूरत बात - इसका तय भी समाज ही करता है कि कौन कितना अच्छा और कितना खराब है। मान लो एक बेटा अपनी माँ को महीने का बीस हजार भेज देता है,पर पाँच मिनट बात नहीं करता -फिर भी ये समाज कहता है वाह, कितना केयरिंग बेटा है। वही एक बेटा अगर अपनी माँ के पास बैठकर उसके पैर दबा दे,उसकी बात सुन ले, पर पैसे न दे पाए-तो वही समाज कहेगा नालायक है उसे बोल-बोलकर अंदर ही अंदर मार देता है। अब तो शादी-विवाह,प्यार-मोहब्बत सब जैसे पैसे पर निर्भर कर रहा है। सबसे बड़ा दुःख ये कि हम जिसके लिए तन,मन,धन से मेहनत किए, उनको हमारी मेहनत से ज्यादा गिफ्ट की परवाह थी। हमारी भावनाओं की कद्र न करते हुए,दूसरों के दिए गिफ्ट से तुलना करने लगे।इसलिए अब लगता है कि इस आधुनिक दुनिया में दिखावटी इंसान ही जी पाएंगे, दिल के सच्चे लोग अंदर ही अंदर मर रहे हैं। भले लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं,लेकिन मेरा आज भी मानना है कि किसी का सम्मान करो तो दिल से करो, दिखावे से नहीं। क्योंकि जो लोग आज गिफ्ट से तुम्हें जज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे बुरे वक्त में सबसे पहले वही गायब होंगे। इसलिए जो तुम्हारे बुरे वक्त में तन-मन-धन से साथ देगा, वो बिना गिफ्ट के भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। इसलिए गिफ्ट से नहीं बल्कि व्यवहार देखकर रिश्तें निभाए।।

महिला आरक्षण,लोकसभा सीटों का विस्तार और लोकतंत्र की कसौटी

प्रतिनिधित्व बढ़े,लेकिन क्या जनता पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ?

प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी समावेशी भावना है। यह व्यवस्था केवल शासन चलाने का माध्यम नहीं,बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का संवैधानिक वादा भी है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इसी वादे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम रही है। इसलिए महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार स्वाभाविक रूप से स्वागत योग्य माना जाता है। यह केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं,बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता का भी प्रश्न है।

लेकिन महिला आरक्षण की इस ऐतिहासिक पहल के साथ एक नई बहस भी जन्म ले चुकी है। क्या महिलाओं को 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के लिए लोकसभा की कुल सीटों में भारी वृद्धि आवश्यक है? क्या मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती? यह प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि आर्थिक,प्रशासनिक और संवैधानिक दृष्टि से भी गंभीर है।

सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों की संभावित वृद्धि दो अलग-अलग विषय हैं। महिला आरक्षण का संबंध निर्वाचित सीटों के आरक्षण से है, जबकि लोकसभा की सीटों का विस्तार भविष्य के परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़ा हुआ विषय है। फिर भी आम नागरिक के मन में यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि यदि आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना है,तो क्या इसके लिए संसद का आकार बढ़ाना अनिवार्य है?

लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल अधिक सांसद होना नहीं है। लोकतंत्र की सफलता इस बात से मापी जाती है कि जनप्रतिनिधि कितने उत्तरदायी हैं,संसद में कितनी गंभीर बहस होती है,कानून कितनी गुणवत्ता से बनते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कितना प्रभावी ढंग से होता है। यदि केवल संख्या बढ़ाने से लोकतंत्र मजबूत होता,तो दुनिया के सबसे बड़े संसद वाले देश स्वतः सबसे बेहतर लोकतंत्र भी होते। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है।

भारत में आज भी लाखों लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार,कृषि संकट और आधारभूत सुविधाओं जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में यदि संसद की संख्या बढ़ती है,तो जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या इससे शासन अधिक प्रभावी होगा या केवल सरकारी खर्च बढ़ेगा? प्रत्येक सांसद के साथ वेतन,कार्यालय,कर्मचारी, आवास, यात्रा,सुरक्षा,संसदीय संसाधन और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी जुड़ा होता है। इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाने का निर्णय केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वित्तीय निर्णय भी है।

हालांकि इस विषय पर यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि अक्सर सार्वजनिक चर्चा में सांसदों के वेतन और सरकारी खर्च के बारे में कई दावे किए जाते हैं, जिनके वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी आर्थिक तर्क को प्रमाणित सरकारी आँकड़ों के आधार पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक विमर्श तथ्यों पर आधारित होना चाहिए,अतिशयोक्ति पर नहीं।

महिला आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि बिना संवैधानिक गारंटी के राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त टिकट नहीं देंगे। पिछले सात दशकों का अनुभव भी यही बताता है कि अधिकांश दल चुनावों में महिलाओं को सीमित अवसर देते रहे हैं। इसलिए आरक्षण आवश्यक है। यह तर्क मजबूत और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित है। लेकिन दूसरी ओर एक चिंता यह भी व्यक्त की जाती है कि क्या आरक्षण का लाभ वास्तव में समाज के अंतिम पायदान की महिलाओं तक पहुंचेगा? भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ना आज भी अत्यधिक संसाधन-आधारित प्रक्रिया है। ऐसे में संभावना रहती है कि टिकट वितरण में राजनीतिक परिवारों, प्रभावशाली नेताओं,आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों अथवा पहले से प्रसिद्ध व्यक्तियों को प्राथमिकता मिले।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

यदि ऐसा होता है,तो ग्रामीण,गरीब, किसान,मजदूर और मध्यमवर्गीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक नहीं बढ़ पाएगा।

यह चुनौती केवल महिला आरक्षण की नहीं,बल्कि भारतीय राजनीति की समग्र संरचना की है। जब तक राजनीतिक दल अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर नहीं देंगे,तब तक केवल संवैधानिक आरक्षण से अपेक्षित परिवर्तन सीमित रह सकता है। वास्तविक महिला सशक्ति करण का अर्थ केवल संसद तक पहुँचाना नहीं, बल्कि निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति देना भी है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। लगभग सभी दल महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन टिकट वितरण,संगठनात्मक पदों और शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित दिखाई देती है। यदि राजनीतिक दल स्वयं अपनी कार्यप्रणाली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ, तो लोकतांत्रिक संस्कृति अधिक मजबूत होगी।

लोकसभा की सीटों में संभावित वृद्धि का एक दूसरा आयाम संघीय संतुलन भी है। परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन हो सकता है। इससे विभिन्न राज्यों के बीच राजनीतिक शक्ति का संतुलन प्रभावित होने की संभावना पर भी विशेषज्ञ चर्चा करते रहे हैं। इसलिए यह केवल संसद की संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था का भी विषय है। ऐसे निर्णय व्यापक राष्ट्रीय सहमति और गंभीर विमर्श के आधार पर ही लिए जाने चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र की एक और चुनौती है–जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का घटता विश्वास। संसद में व्यवधान,राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, विधेयकों पर सीमित चर्चा और चुनावी राजनीति का बढ़ता प्रभाव लोगों के मन में यह प्रश्न पैदा करता है कि क्या लोकतांत्रिक संस्थाएँ अपनी सर्वोत्तम क्षमता से काम कर रही हैं? यदि जनता पहले से ही प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर प्रश्न उठा रही है,तो संख्या बढ़ाने से पहले जवाबदेही बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

लोकतंत्र में गुणवत्ता, संख्या से अधिक महत्वपूर्ण होती है। यदि संसद की कार्यवाही अधिक प्रभावी हो,संसदीय समितियाँ बेहतर ढंग से काम करें,सांसद अपने क्षेत्रों में अधिक सक्रिय रहें और कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने, तो जनता का विश्वास स्वतः बढ़ेगा। केवल अधिक सांसद होने से लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी नहीं हो जाता।

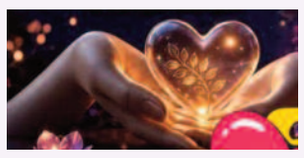

महिला आरक्षण को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी आवश्यक है। महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से संसद में शिक्षा,स्वास्थ्य,पोषण,महिला सुरक्षा, बाल अधिकार,सामाजिक न्याय और परिवार से जुड़े विषयों पर अधिक संवेदनशील बहस होने की संभावना रहती है। विश्व के अनेक देशों के अनुभव बताते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति-निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल होते हैं। इसलिए महिला प्रतिनिधित्व का विस्तार लोकतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है।

लेकिन इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहे। महिलाओं को केवल चुनाव लड़ने का अवसर ही नहीं, बल्कि संसदीय समितियों,मंत्री परिषदों,नीति आयोगों और राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व में भी समान अवसर मिलें। तभी आरक्षण अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा।

यदि वर्तमान 543 सीटों के भीतर 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सकता है,तो यह विकल्प भी गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए। इससे महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा और अतिरिक्त प्रशासनिक खर्च की आवश्यकता भी कम होगी। वहीं यदि भविष्य में परिसीमन के संवैधानिक प्रावधानों के कारण सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उसके औचित्य, आर्थिक प्रभाव और लोकतांत्रिक लाभों पर भी सरकार को स्पष्ट और पारदर्शी संवाद करना चाहिए।

लोकतंत्र में असहमति विरोध नहीं होती, बल्कि नीति निर्माण को बेहतर बनाने का माध्यम होती है। महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए भी उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर प्रश्न उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। इसी प्रकार सीटों की संभावित वृद्धि का समर्थन या विरोध भी तथ्यों,संवैधानिक प्रावधानों और सार्वजनिक हित के आधार पर होना चाहिए,न कि केवल राजनीतिक आग्रहों के आधार पर।

अंततः भारत को ऐसे लोकतंत्र की आवश्यकता है जहाँ प्रतिनिधित्व भी बढ़े,जवाबदेही भी मजबूत हो और सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित हो। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को समृद्ध बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु यह भी उतना ही आवश्यक है कि लोकतांत्रिक सुधार जनता के विश्वास,आर्थिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़ें। महिला आरक्षण का उद्देश्य अधिकार देना है, न कि केवल संख्या बढ़ाना। यदि यह उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था के भीतर अधिक प्रभावी ढंग से पूरा हो सकता है,तो उस विकल्प पर गंभीर विचार होना चाहिए। और यदि सीटों की संख्या बढ़ाना अपरिहार्य हो,तो उसके पीछे के कारण,लाभ और वित्तीय प्रभाव जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखे जाने चाहिए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता का विश्वास है,और यह विश्वास तभी मजबूत होता है जब निर्णय संवाद,तर्क और उत्तर दायित्व के साथ लिए जाएँ।

यूज्ड ईवी : बदलती सोच,बदलता बाजार और बदलता भारत

हरित विकास का लोकतंत्रीकरण: अब इलेक्ट्रिक सफर सबके लिए...

हरित क्रांति का नया चेहरा: पुनः उपयोग,पुनः विश्वास और पुनः विकास

प्रो.रितेश जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

हर बदलाव नई चीज़ों से नहीं,नई सोच से जन्म लेता है। भारत में यूज्ड इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से बढ़ता बाजार इसका प्रमाण है।

यह केवल ऑटो मोबाइल उद्योग की रफ्तार नहीं,बल्कि विकास को उपभोग नहीं,उपयोगिता की कसौटी पर परखने का संकेत है। जिस वाहन को कल तक सेकंड हैंड कहकर नजरअंदाज किया जाता था,वही आज स्वच्छ पर्यावरण,किफायती परिवहन और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का भरोसेमंद वाहक बन गया है। यूज्ड ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) बाजार की यह उड़ान महज़ आंकड़ों की कहानी नहीं,बल्कि उस भारत की पहचान है,जो सीमित संसाधनों में भी भविष्य गढ़ना जानता है।

बदलाव की असली पहचान तब होती है,जब वह आम आदमी की पहुँच में उतर आए। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ यही हो रहा है। नई ईवी कारों और दोपहिया वाहनों की ऊँची कीमत मध्यम वर्ग के लिए अब भी चुनौती है,लेकिन यूज्ड ईवी बाजार ने यह बाधा तोड़ दी है। कम कीमत,पर्याप्त बची हुई बैटरी लाइफ और आसान फाइनेंसिंग ने लाखों लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन सुलभ कर दिए हैं। आर्थिक सीमाओं में बंधे लोग अब पर्यावरण-अनुकूल विकल्प चुन सकते हैं। पहली इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर अब केवल संपन्न वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक की पहुँच में है।

पूँजी हमेशा वहीं जाती है,जहाँ भविष्य दिखाई देता है। यूज्ड ईवी बाजार ने वित्तीय संस्थानों का यही भरोसा जीता है। फाइनेंस कंपनियाँ इसे केवल ऋण का नया क्षेत्र नहीं,बल्कि कम जोखिम और बेहतर प्रतिफल वाला निवेश मान रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता और निरंतर बढ़ती मांग ने इस बाजार को मजबूत आधार दिया है। जब निवेश विश्वास के साथ बढ़ता है,तो स्पष्ट होता है कि बाजार क्षणिक उत्साह नहीं, स्थायी संभावनाओं पर टिका है। यही भरोसा आने वाले वर्षों में यूज्ड ईवी बाजार की रफ्तार को और तेज करेगा।

सबसे बड़ा लाभ बाजार का नहीं,सांसों का है। यूज्ड ईवी बाजार की असली उपलब्धि यही है कि हर इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता को थोड़ा और कम करता है। जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण से जूझते भारतीय शहरों में यह बदलाव किसी शोरगुल वाले अभियान से नहीं,बल्कि एक मौन हरित क्रांति के रूप में सामने आया है। इसकी ताकत नारों में नहीं, व्यवहार में है। हर पुरानी इलेक्ट्रिक कार या स्कूटर को मिला नया जीवन वातावरण में प्रदूषण घटाने और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक ठोस कदम है।

विकास का भविष्य नए संसाधन जुटाने में नहीं,पुराने संसाधनों के बेहतर उपयोग में है। यूज्ड ईवी बाजार इसी सोच का विस्तार है। किसी पुराने इलेक्ट्रिक वाहन का पुनः उपयोग केवल वाहन नहीं बचाता, बल्कि उसके निर्माण में लगी ऊर्जा और खनिज भी बचाता है। नई बैटरियों के उत्पादन में भारी संसाधन लगते हैं,जबकि मौजूदा बैटरी का उपयोग पर्यावरणीय दबाव घटाता है। यही परिपत्र अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

आधार है,जहाँ वस्तुएँ खत्म नहीं होतीं, नया उपयोग पाती हैं। इसलिए यूज्ड ईवी बाजार केवल सस्ता विकल्प नहीं,संसाधन संरक्षण का प्रभावी माध्यम भी है।

हर उड़ान की परीक्षा उसकी ऊँचाई नहीं, स्थिरता होती है। यूज्ड ईवी बाजार के सामने यही चुनौती है। बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद बैटरी की गुणवत्ता सबसे बड़ा प्रश्न बनी हुई है। हर खरीदार के मन में सवाल है कि बची हुई बैटरी कितने वर्षों तक भरोसेमंद रहेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सीमित विस्तार, प्रशिक्षित सर्विस सेंटरों की कमी और बैटरियों के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) का कमजोर ढाँचा इसकी रफ्तार रोक सकता है। इन कमियों का समाधान नहीं हुआ, तो आज का उत्साह कल अविश्वास में बदल सकता है। तकनीकी बदलाव की सफलता केवल बिक्री नहीं, मजबूत तंत्र से तय होती है।

समाधान बिखरे प्रयासों में नहीं,साझा संकल्प में है। सरकार,वाहन निर्माता और वित्तीय संस्थानों को मिलकर आगे बढ़ना होगा। बैटरियों का स्पष्ट स्टैंडर्डाइजेशन, सेकंड लाइफ बैटरियों के सुरक्षित उपयोग की नीति,यूज्ड ईवी के लिए विशेष इंश्योरेंस,प्रमाणित बैटरी हेल्थ रिपोर्ट और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क इस क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें हैं। सरकार दूरदर्शी नीति बनाए, वाहन कंपनियाँ भरोसेमंद सेवाएँ दें और फाइनेंस कंपनियाँ आसान वित्त दें,तो यूज्ड ईवी बाजार केवल कारोबार नहीं,भारत की हरित अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। टिकाऊ विकास तभी संभव है,जब नीति, तकनीक और वित्त एक दिशा में बढ़ें।

हरित विकास तभी सार्थक है,जब वह आम आदमी की पहुँच में हो। यूज्ड ईवी बाजार ने यह संभव किया है। जो हरित तकनीक कभी सम्पन्न वर्ग तक सीमित थी,वह अब मध्यम वर्ग का विकल्प बन रही है। सीमित आय वाला परिवार कम कीमत में पहली इलेक्ट्रिक कार,स्कूटर या बाइक खरीदकर केवल ईंधन नहीं बचाता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा में अपना योगदान देता है। यही लोकतांत्रिक हरित क्रांति है,जहाँ पर्यावरण संरक्षण विशेषाधिकार नहीं,जनभागीदारी बन जाता है। यूज्ड ईवी बाजार ने साबित किया है कि टिकाऊ विकास महँगा नहीं,समझदारी का विकल्प हो सकता है।

भविष्य उन देशों का होता है,जो संसाधनों का मूल्य समझते हैं। यूज्ड ईवी बाजार ने दिखाया है कि विकास और पर्यावरण साथ चल सकते हैं। मजबूत नीतियाँ, बेहतर आधारभूत ढाँचा और विश्वसनीय तकनीक मिली, तो भारत ग्रीन मोबिलिटी में विश्व नेतृत्व हासिल कर सकता है। तब दुनिया भारत को केवल बड़े वाहन बाजार के रूप में नहीं,बल्कि संसाधनों के पुनः उपयोग को विकास का आधार बनाने वाले देश के रूप में पहचानेगी। इस बदलाव का नायक कोई नया वाहन नहीं, बल्कि वही पुराना वाहन है,जिसे समाज ने नया उद्देश्य दिया। कल की सेकंड हैंड कार आज पर्यावरण की प्रहरी है। यही सोच कल के भारत की पहचान बन सकती है।

यहाँ हर शख्स झूठा है

अशोक पटेल आशु
शिवरीनारायण
छत्तीसगढ़

लोग मानते जा रहे हैं,
अंधाधुन होके मानते जा रहे हैं
इससे बेखबर,हों आँखों में
सभी पट्टी बांधे जा रहे हैं।
सच कोई सुनता नही है,
सच कोई बताने वाला नही
यहाँ हरेक शख्स झूठा है,
यही सच जानते आ रहे हैं।

यह दुनिया दिखावे की है,इसी की
यहाँ बोलबाला है
अंदर में बेईमानी है,और नियत में
बस छलावा ही है
कोई करे तो करे किस पर
यकींन,जताने वाला नही
यहाँ गैर तो गैर हैं,सब अपनों से ही
लुटाये जा रहे हैं।

यहाँ का हर एक शख्स,
कई-कई राज छुपाये हुए हैं
हर शख्सियत ईमान और इंसानियत
दफनाये हुए हैं
कोई ईमान पर चलता नही,
कोई मानने वाला नही
यहाँ हर कोई बेईमानी पर,
मिशाल बनाये जा रहें हैं।

पत्तों से घाव

गरिमा राकेश गौत्तम
कोटा,राजस्थान

वृक्षों के पत्तों से
होते है कुछ घाव
प्रकृति उन पर
समय की धूल की
परत तो चढ़ा देती हैं
लेकिन
जब होती है यादों की
बरसात तो
छम छम बूंदों से
धूल धुल जाती है
फिर ......
पत्ते भी हरे -हरे
घाव भी हरे -हरे ।

विदेश से भारत की संप्रभुता-सुरक्षा के खिलाफ डिजिटल वार

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी देशों को कमजोर करने के लिए सीमा पर सेना उतारी जाती थी,अब वही काम मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिए किया जा रहा है। इस युद्ध में न तो टैंक दिखाई देते हैं और न ही मिसाइलें,लेकिन इसका असर किसी पारंपरिक युद्ध से कम नहीं होता। इसका लक्ष्य दुश्मन के शहरों पर कब्जा करना नहीं,बल्कि उसके समाज में अविश्वास,भय और विभाजन पैदा करना होता है। भारत,जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ सबसे बड़ा डिजिटल समाज भी बन चुका है,पिछले एक दशक से इसी अदृश्य युद्ध का प्रमुख निशाना बना हुआ है। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक हो चुकी है,जबकि सोशल मीडिया से जुड़े लोगों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। हर दिन करोड़ों भारतीय मोबाइल पर समाचार देखते हैं, राय बनाते हैं और उसे आगे भी भेजते हैं। यही वजह है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है,जहां सूचना को हथियार बनाकर सामाजिक माहौल प्रभावित करने की सबसे अधिक कोशिश होती है। सुरक्षा एजेंसियां कई बार संकेत दे चुकी हैं कि सीमा पार बैठे संगठित नेटवर्क भारतीय नामों,तस्वीरों और स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल कर ऐसे फर्जी खाते तैयार करते हैं, जिन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने बैठा व्यक्ति वास्तव में किसी दूसरे देश से अभियान चला रहा है।

इस डिजिटल हमले की पहली गंभीर झलक 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में दिखाई दी। हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान का नहीं,बल्कि दूसरे देश का एक पुराना वीडियो उत्तर प्रदेश का बताकर प्रसारित किया गया। जांच में वीडियो फर्जी निकला,लेकिन तब तक समाज में तनाव फैल चुका था। यही वह दौर था जब पहली बार यह महसूस किया गया कि मोबाइल स्क्रीन पर चलने वाला झूठ जमीन पर खून-खराबे की वजह बन सकता है। इसके बाद 2017 और 2018 में बच्चा चोरी की अफवाहों ने पूरे देश को झकझोर दिया। व्हाट्सऐप पर कुछ सेकंड के वीडियो और झूठे संदेशों ने ऐसी दहशत फैलाई कि असम, महाराष्ट्र,कर्नाटक,झारखंड, त्रिपुरा और तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भीड़ ने निर्दोष लोगों को बच्चा चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस जांच में अधिकांश मामलों में कोई संगठित बच्चा चोरी गिरोह नहीं मिला,लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि सच की कोई कीमत नहीं रह गई थी। कोरोना महामारी के दौरान यह सूचना युद्ध और खतरनाक हो गया। किसी समुदाय को संक्रमण फैलाने वाला बताया गया,कहीं झूठे घरेलू इलाज वायरल किए गए,तो कहीं वैक्सीन को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई गईं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे इन्फोडेमिक कहा, यानी ऐसी महामारी जिसमें बीमारी से ज्यादा झूठ फैलता है। भारत में भी करोड़ों लोगों तक ऐसे संदेश पहुंचे जिनका चिकित्सा विज्ञान से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून,दिल्ली हिंसा और किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पूरी तरह राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया। वास्तविक मुद्दों के साथ-साथ हजारों ऐसे वीडियो और तस्वीरें साझा की गईं जिनका घटना से कोई संबंध नहीं था। कुछ पुराने वीडियो नए बताकर वायरल किए गए तो कुछ तस्वीरों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया गया। किसान आंदोलन के दौरान तथाकथित टूलकिट विवाद ने यह सवाल खड़ा किया कि क्या भारत के आंतरिक आंदोलनों को विदेशी डिजिटल नेटवर्क दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने कई डिजिटल कड़ियों की जांच की और यह स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया अब केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि रणनीतिक अभियान चलाने का औजार भी बन चुका है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

52 लाख के कथित गबन का बोझ या सिस्टम का दबाव?

सात माह बाद बैंक प्रबंधक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस,कई सवाल बरकरार

पत्नी ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप,पुलिस ने दर्ज की एफआईआर,लेकिन जांच...जवाबदेही और वसूली प्रक्रिया पर भी उठा गंभीर प्रश्न

-संवाददाता-
अंबिकापुर/सीतापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सेवा सहकारी समिति केरजू के प्रबंधक दिनेश गुप्ता की आत्महत्या के लगभग सात माह बाद सीतापुर पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक भूपेंद्र सिंह परिहार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। एफआईआर मृतक की पत्नी, परिजनों, अन्य गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मर्ग जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों के आधार पर दर्ज की गई है।

मामले ने सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली,कर्मचारियों पर बनाए जाने वाले प्रशासनिक दबाव और वित्तीय अनियमितताओं से निपटने के तौर-तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि पुलिस जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि पूरे तंत्र की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न माना जाएगा। वहीं

आरोपित पक्ष का पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में सामने आना अभी बाकी है।

52 लाख के कथित गबन का मामला बना तनाव की वजह : पुलिस के अनुसार मूलजिमापारा निवासी 55 वर्षीय दिनेश गुप्ता ग्राम केरजू सेवा सहकारी समिति में प्रबंधक थे। उन पर करीब 52 लाख रुपये के कथित गबन का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक लगातार राशि जमा करने का दबाव बना रहे थे तथा ऐसा नहीं करने पर नौकरी से हटाने,विभागीय कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही थी। मृतक की पत्नी सुनीता गुप्ता ने अपने बयान में कहा कि इसी लगातार मानसिक दबाव के कारण उनके पति अवसाद में चले गए थे और अंततः 25-26 दिसंबर 2025 की रात उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि 52 लाख रुपये के कथित गबन के मूल मामले की निष्पक्ष जांच भी पूरी हो। यदि वास्तव में वित्तीय अनियमितता हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, राशि का नुकसान कैसे हुआ और उसकी वसूली या जांच किस स्थिति में है–इन बिंदुओं पर भी अब तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

सात माह तक क्यों चलता रहा इंतजार?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना दिसंबर 2025 में हुई,लेकिन एफआईआर जुलाई 2026 में दर्ज हुई। पुलिस का कहना है कि मर्ग जांच,पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अपराध दर्ज किया गया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है,लेकिन इतने लंबे अंतराल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि शुरुआती जांच में मानसिक प्रताड़ना के संकेत मिल रहे थे तो कार्रवाई में सात महीने का समय क्यों लगा? क्या जांच में देरी ने साक्ष्यों और गवाहों को प्रभावित किया? इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं।

गबन की जांच और मानसिक प्रताड़ना–दो अलग पहलू

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी कर्मचारी पर वित्तीय अनियमितता का संदेह हो तो विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जानी चाहिए। लेकिन जांच के दौरान किसी कर्मचारी पर ऐसा मानसिक दबाव नहीं बनाया जा सकता जिससे उसका जीवन संकट में पड़ जाए।

अब जांच की दिशा पर रहेगी नजर

एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना आगे बढ़ा रही है। जांच में यह स्पष्ट होगा कि क्या वास्तव में आरोपी अधिकारी के व्यवहार और कथित मानसिक दबाव का सीधा संबंध आत्महत्या से था या नहीं। न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य ही अंततः इस मामले की दिशा तय करेंगे। यह मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं बल्कि सरकारी और सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के साथ व्यवहार,जवाबदेही और प्रशासनिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा माना जा रहा है। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो यह संदेश जाएगा कि प्रशासनिक अधिकार का दुरुपयोग किसी कर्मचारी के जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। वहीं यदि आरोप सिद्ध नहीं होते तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पूरे घटनाक्रम की वास्तविक जिम्मेदारी आखिर किस पर थी।

बंद कूलर में दौड़ा करंट,युवक की मौत

नहाकर कमरे में गया था युवक,कूलर छूते ही लगा जोरदार झटका,अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

शहर में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने के कुछ समय बाद बंद पड़े कूलर में अचानक करंट आ गया। युवक जैसे ही नहाकर कमरे में पहुंचा और कूलर को छुआ, उसे तेज करंट का झटका लगा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को दिए बयान में मृतक के पिता नारायण मंडल ने बताया कि उनका पुत्र रोविन मंडल एसएससीएल बिजुरी में कार्यरत था और 9 जुलाई की रात घर आया था। 10 जुलाई की दोपहर करीब तीन बजे बारिश के दौरान घर के पास लगे बिजली ट्रांसफार्मर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। कुछ देर बाद रोविन नहाकर अपने कमरे में गया और कपड़े पहनते समय बंद पड़े कूलर पर हाथ रख दिया। कूलर को छूते ही उसे तेज करंट का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो देखा कि उसके नाक और कान से खून निकल रहा था तथा वह बेहोश पड़ा था। आनन-फानन में उसे मिशन अस्पताल ले जाया गया,जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने के बाद किसी तकनीकी खराबी के कारण बंद कूलर में करंट आ गया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसा बिजली आपूर्ति में आई गड़बड़ी के कारण हुआ या किसी अन्य तकनीकी कारण से।

स्कूटी की डिक्की से 40 हजार रुपये पार नाश्ता करने होटल गया था उपसरपंच

-संवाददाता-
बतौली,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

बैंक से 40 हजार रुपये निकालने के कुछ ही मिनट बाद स्कूटी की डिक्की से नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात शुक्रवार दोपहर बगीचा रोड स्थित विकास होटल के सामने हुई। पीड़ित होटल में नाश्ता करने गया था,इसी दौरान अज्ञात बदमाश डिक्की से रुपयों से भरा झोला लेकर फरार हो गए। शिकायत पर बतौली पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार ग्राम शिवपुर निवासी एवं उपसरपंच ओमप्रकाश गुप्ता (45) ने सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक,बतौली से खेती के कार्य के लिए 40 हजार रुपये निकाले थे। उन्होंने नकदी को लाल रंग के झोले में रखकर अपनी स्कूटी की डिक्की में रखा और पास ही स्थित विकास होटल में नाश्ता करने चले गए। कुछ देर बाद जब वे लौटे तो स्कूटी की डिक्की खुली मिली। अंदर रखा रुपयों से भरा झोला गायब था, जबकि बैंक पासबुक नीचे पड़ी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल बतौली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

सरगुजा की सड़कों पर मौत का तांडव : एक ही रात में चार जिंदगियां खत्म,आखिर कब जागेगा प्रशासन?

मैनपाट में आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक,तीन युवकों की मौत,बतौली में ट्रक ने ली महिला की जान,सड़क सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले में शुक्रवार की रात हुए दो भीषण सड़क हादसों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन की तमाम बैठकों,अभियानों और दावों का जमीनी असर कहां दिखाई देता है? मैनपाट और बतौली में हुए दो अलग-अलग हादसों में तीन युवकों और एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। इन घटनाओं ने कई परिवारों की खुशियां पलभर में छीन लीं।

मैनपाट की सड़क बनी मौत का मैदान कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के नवापारा–नर्मदापुर मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर इतनी भयावह थी कि तीन युवकों की जान चली गई। सीतापुर के मलसायपारा कोट निवासी विफल माझी (21) और गुड्डू राम (22) मैनपाट घूमकर लौट रहे थे। दूसरी ओर लुण्ड्रा निवासी अर्जुन लोहार (23) अपने ससुराल नर्मदापुर जा रहा था। तेज रफ्तार में हुई सीधी भिड़ंत ने तीनों परिवारों को गहरे शोक में डुबो दिया। गुड्डू राम और अर्जुन लोहार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल विफल माझी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एनएच पर बेलगाम भारी वाहन, कब होगी सख्ती? बतौली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार लंबे समय से चिंता का विषय रही है। कई बार हादसे होने के बावजूद ओवरस्पीड ट्रकों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिखता। दुर्घटना के बाद चालक का फरार हो जाना भी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।

बयान से नहीं,जमीन पर बदलाव चाहिए : हाल के महीनों में जिला सड़क सुरक्षा समिति की कई बैठकें हुईं, अधिकारियों ने दुर्घटनाएं कम करने के दावे भी किए,लेकिन वास्तविकता यह है कि सड़कें लगातार लोगों की जान ले रही हैं। यदि हादसे उसी रफ्तार से होते रहे तो बैठकों और निर्देशों का औचित्य भी सवालों के घेरे में रहेगा। चार मौतें केवल आंकड़े नहीं हैं,बल्कि चार परिवारों की ऐसी त्रासदी हैं जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अब जरूरत केवल जांच और मर्ग कायम करने की नहीं,बल्कि सड़क सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर समीक्षा, जवाबदेही तय करने और प्रभावी कार्रवाई की है, ताकि किसी और परिवार को ऐसी असमय मौत का दर्द न झेलना पड़े।

बतौली में अज्ञात ट्रक का कहर

इसी दिन बतौली थाना क्षेत्र के सेदम बाजार के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। हादसे में रीता एक्का (48) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति सुखन एक्का घायल हो गए। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

सिर्फ कार्रवाई नहीं...जवाबदेही भी तय होनी चाहिए...

हर बड़े हादसे के बाद पुलिस तेज रफ्तार, लापरवाही या अंधेरे को कारण बताकर जांच शुरू करने की बात कह देती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि लगातार तेज रफ्तार हादसों की वजह बन रही है तो उसे रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? मैनपाट जैसे पर्यटन स्थल पर हर सप्ताह बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन रात के समय सड़क सुरक्षा,पर्याप्त रोशनी,गति नियंत्रण और पुलिस निगरानी की व्यवस्था अब भी अपर्याप्त नजर आती है।

ब्लैक स्पॉट सुधारें,सड़क हादसे रोकें : आईजी

यातायात समीक्षा बैठक में दिए निर्देश,डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम और ई-चालान व्यवस्था पर भी जोर

सरगुजा रेंज में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा ने शनिवार को यातायात नोडल अधिकारियों एवं ई-डीएआर के डीआरएम सदस्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ब्लैक स्पॉट,डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम,ई-चालान व्यवस्था तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। आईजी ने निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर संबंधित विभागों के समन्वय से सड़क सुधार,चेतावनी संकेतक,रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड, रोड मार्किंग और रंबल स्ट्रिप्स जैसे सुरक्षा उपाय प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने बताया कि एनएच-43 के नावापारा,सम्राट पेट्रोल पंप और लुण्ड्रा चौक पर किए गए सुधारों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसी मॉडल को रेंज के अन्य जिलों में भी लागू करने के निर्देश दिए गए। बैठक में डायल-112 के रिस्पॉन्स टाइम को और बेहतर बनाने पर जोर देते हुए आईजी ने कहा कि सड़क हादसों में प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है। इसलिए पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाए और निजी एम्बुलेंस सेवाओं में जीपीएस ट्रैकिंग एवं बेहतर समन्वय विकसित किया जाए। उन्होंने सभी जिलों में ई-चालान प्रणाली का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने,जशपुर की तर्ज पर गांवों,स्कूल-कॉलेजों, हाट-बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाने तथा केंद्र सरकार की 'राह-वीर योजना' का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए तकनीक,जागरूकता और त्वरित आपातकालीन सहायता–तीनों पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

सरगुजा पुलिस की विवेचना अब होगी हाईटेक : 102 विवेचकों को मिले स्मार्ट मोबाइल, ई-साक्ष्य संकलन होगा तेज और पारदर्शी

नई तकनीक से बदलेगी जांच की तस्वीर,घटना स्थल से रियल टाइम फोटो-वीडियो और डिजिटल रिपोर्टिंग होगी मानकीकृत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

अपराध अनुसंधान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और नई आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में सरगुजा पुलिस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा ASUMP Scheme 2025-26 के तहत उपलब्ध कराए गए 102 सैमसंग स्मार्ट मोबाइल जिले के विवेचकों को वितरित किए गए। इन मोबाइलों के माध्यम से अब विवेचना प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक,पारदर्शी और तकनीक आधारित होगी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंबिकापुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) ने जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ 102 विवेचकों को स्मार्ट मोबाइल प्रदान किए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

ई-साक्ष्य संकलन को मिलेगा नया आयाम

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से विवेचना की गुणवत्ता और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'ई-साक्ष्य' का त्वरित,सुरक्षित और प्रमाणिक संकलन बेहद आवश्यक है। स्मार्ट मोबाइल मिलने से विवेचक घटनास्थल पर ही डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित तरीके से एकत्रित कर सकेंगे।

घटनास्थल से होगी रियल टाइम डिजिटल रिपोर्टिंग

इन हाईटेक मोबाइलों की सहायता से विवेचक अब घटनास्थल की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें,ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, लोकेशन आधारित जानकारी तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर सकेंगे। इससे जांच प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित,मानकीकृत और न्यायालय में साक्ष्यों की विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

विशेष प्रशिक्षण और मॉनिटरिंग की भी होगी व्यवस्था

मोबाइल वितरण के बाद पुलिस विभाग विवेचकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें उन्हें डिजिटल साक्ष्य संकलन, ई-साक्ष्य प्रबंधन तथा डेटा सुरक्षा के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही तकनीकी सहायता और डेटा सुरक्षा मानकों के पालन के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू किया जाएगा।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

सरगुजा पुलिस का मानना है कि तकनीक आधारित विवेचना से अपराधों की जांच में गति आएगी,साक्ष्यों की गुणवत्ता बेहतर होगी और न्यायिक प्रक्रिया अधिक मजबूत बनेगी। आधुनिक संसाधनों से लैस विवेचक अब अधिक दक्षता के साथ अपराध अनुसंधान कर सकेंगे,जिससे आम जनता को भी बेहतर और त्वरित न्याय मिलने में सहायता मिलेगी।

भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने आयोजित किया निःशुल्क विधिक सहायता शिविर,अधिवक्ताओं को सिखाया डिजिटल तकनीक का हुनर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ जिला सरगुजा द्वारा आयोजित निःशुल्क विधिक सहायता शिविर और डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिवक्ताओं को कानूनी सहायता के साथ-साथ आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन परीक्षा देकर प्राप्त किए प्रमाण पत्र : कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया थे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला संयोजक जन्मेजय पाण्डेय के नेतृत्व में निःशुल्क विधिक सहायता शिविर के साथ हुई, जिसके बाद डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम का सत्र आयोजित किया गया। इसमें डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के जिला संयोजक मयंक जायसवाल और पीयूष त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं को सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन और संगठनात्मक कार्यों को तकनीक के जरिए गति देने का प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के बाद उपस्थित अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन परीक्षा दी और मेधावी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रमाण पत्र प्राप्त किए।

तकनीक से जनसेवा का संकल्प : भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि आज के दौर में तकनीक के बिना कार्यकुशलता संभव नहीं है। विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम अधिवक्ताओं को डिजिटल युग में सक्षम बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इस तकनीक के उपयोग से अधिवक्ता न केवल अपने पेशेवर काम को बेहतर कर सकेंगे, बल्कि संगठन की गतिविधियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को भी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुँचा सकेंगे।

ये रहे उपस्थित : कार्यक्रम में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्याम लाल गुप्ता,धनंजय मिश्रा,प्रदेश सदस्य संजीव कुमार सेठ,नीलेश सिंह,आशा जायसवाल,सुरेंद्र पाण्डेय,बलराम सोनी,अमरेंद्र गुप्ता,ज्योति मंडल,साक्षी सिंह,नीलम केशरवानी,अपूर्वा विश्वकर्मा, सुष्मिता चक्रवर्ती,विवेक पाण्डेय,अश्वनी पाण्डेय,निशांत सिन्हा,दिनेश प्रसाद साहू,वीरेंद्र कुमार जायसवाल,प्रभाकर सेठी,सोनू सोनी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पर बल दिया।

C M Y K

कागजों में वत्स पैदा,धरातल पर सन्नाटा! एमसीबी पशुपालन विभाग की योजनाओं पर उठे बड़े सवाल

- कृत्रिम गर्भाधान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा? गांव-गांव सत्यापन हुआ तो खुल सकती हैं कई परतें...
- सरकारी रिकॉर्ड में हजारों वत्स,गांवों में नहीं मिल रहे सबूत,एमसीबी पशुपालन विभाग जांच के घेरे में...
- क्या कागजों में ही बढ़ गया पशुधन? एमसीबी में कृत्रिम गर्भाधान योजना पर करोड़ों के खेल का आरोप...

कोरिया के बाद अब एमसीबी में भी पशुपालन विभाग पर सवाल,कृत्रिम गर्भाधान और वत्स पालन योजना की निष्पक्ष जांच की मांग...

आंकड़ों का खेल या योजनाओं का सच? एमसीबी पशुपालन विभाग के दावों पर उठे गंभीर सवाल...

कागजों में हजारों गर्भाधान,हकीकत में कितने? एमसीबी पशुपालन विभाग की योजनाओं पर जांच की मांग तेज...

कागजों में सफलता,जमीन पर सवाल! करोड़ों की पशुपालन योजनाओं का होगा भौतिक सत्यापन?

एमसीबी में पशुपालन विभाग का 'कागजी विकास'? कृत्रिम गर्भाधान और वत्स पालन योजना पर उठे बड़े सवाल...

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/एमसीबी,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से पशुपालन विभाग के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान एवं वत्स पालन जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है,इन योजनाओं पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं ताकि बेहतर नस्ल के पशु तैयार हों और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके,लेकिन मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

कोरिया जिले में पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों के बाद अब एमसीबी जिले में भी निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता एवं वत्स पालन योजना के आंकड़ों पर संदेह जताया जा रहा है,स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि विभाग द्वारा शासन को भेजे गए हजारों कृत्रिम गर्भाधान और वत्स जन्म के आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते,यदि गांव-गांव जाकर स्वतंत्र भौतिक सत्यापन कराया जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।

सरकारी रिकॉर्ड में हजारों उपलब्धियां,लेकिन धरातल पर तस्वीर अलग?

सूत्रों के अनुसार जिले के सभी विकासखंडों से हर माह बड़ी संख्या में कृत्रिम गर्भाधान, गर्भधारण और वत्स जन्म की रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाती है,इन्हीं आंकड़ों के आधार पर विभाग योजनाओं की सफलता का दावा करता है और सरकारी खर्च का औचित्य भी प्रस्तुत किया जाता है,लेकिन अब आरोप यह है कि इन आंकड़ों का पर्याप्त भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। कई मामलों में केवल कागजी रिपोर्टों के आधार पर उपलब्धियां दर्शा दी गई,यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न होगा।

भौतिक सत्यापन हुआ तो खुल सकती हैं कई परतें...

पशुपालन क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि कृत्रिम गर्भाधान कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे केवल कागजों में दिखाया जा सके,प्रत्येक गर्भाधान का रिकॉर्ड,संबंधित पशुपालक, पशु की पहचान,गर्भधारण और वत्स जन्म तक का पूरा विवरण उपलब्ध होना चाहिए,यदि विकासखंडवार मासिक रिपोर्ट के आधार पर गांव-गांव जाकर पशुपालकों से पूछताछ की जाए,जन्मे वत्सों का मिलान कराया जाए और संबंधित पशुओं का सत्यापन हो,तो वास्तविक स्थिति स्वतः सामने आ जाएगी।

नागपुर क्षेत्र को लेकर सबसे अधिक चर्चा-स्थानीय सूत्रों के अनुसार नागपुर क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान और वत्स जन्म के आंकड़ों को लेकर सबसे अधिक संदेह व्यक्त किया जा रहा है,दावा किया जा रहा है कि जिस संख्या में रिपोर्ट भेजी गई है,उस अनुपात में पशुधन ही उपलब्ध नहीं है, यदि स्वतंत्र जांच में यह बात प्रमाणित होती है तो यह केवल रिकॉर्ड की गलती नहीं बल्कि योजनाओं के संचालन में गंभीर अनियमितता मानी जाएगी।

क्या बिना जांच स्वीकार कर लिए गए आंकड़े?-सबसे बड़ा सवाल विभागीय कार्यप्रणाली पर उठ रहा है। आरोप है कि निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं द्वारा भेजे गए आंकड़ों को संबंधित अधिकारियों ने बिना पर्याप्त सत्यापन के स्वीकार कर लिया,यदि ऐसा हुआ है तो यह स्पष्ट करता है कि निगरानी तंत्र पूरी तरह कमजोर रहा या फिर कागजी उपलब्धियों को ही वास्तविक उपलब्धि मान लिया गया,ऐसे में यह भी जांच का विषय है कि संबंधित अधिकारियों ने मौके पर जाकर कभी सत्यापन किया भी या नहीं।

करोड़ों रुपये की योजनाओं पर उठे पारदर्शिता के सवाल-कृत्रिम गर्भाधान और वत्स पालन योजनाओं के संचालन में हर वर्ष बड़ी मात्रा में सरकारी धन खर्च किया जाता है, इस राशि का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड तैयार करना नहीं बल्कि किसानों तक वास्तविक लाभ पहुंचाना है,यदि योजनाओं के लाभार्थियों का सही सत्यापन नहीं हुआ,तो यह भी जांच का विषय बनता है कि सरकारी राशि का उपयोग वास्तव में किस आधार पर किया गया, विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं होगी,बल्कि स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट और भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।

किसानों तक योजना का पूरा लाभ नहीं पहुंचने का आरोप-ग्रामीण पशुपालकों का कहना है कि सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा,कई किसानों का कहना है कि यदि विभाग के रिकॉर्ड में उनके नाम से कृत्रिम गर्भाधान या वत्स जन्म दर्ज है तो उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है,वहीं कुछ किसानों का कहना है कि वर्षों से योजनाओं के नाम पर केवल कागजी प्रगति दिखाई जा रही है,इसी कारण अब सामाजिक एवं भौतिक सत्यापन की मांग तेज होती जा रही है।

कोरिया के बाद अब एमसीबी भी जांच के घेरे में...

कोरिया जिले में भी पशुपालन विभाग की योजनाओं को लेकर सवाल उठ चुके हैं,अब एमसीबी जिले में भी लगभग उसी प्रकार के आरोप सामने आने से पूरे संभाग में पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर चर्चा शुरू हो गई है,यदि दोनों जिलों की योजनाओं की संयुक्त जांच कराई जाती है तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि योजनाएं वास्तविक रूप से सफल रही हैं या केवल कागजी उपलब्धियों के आधार पर संचालित होती रही हैं।

विशेषज्ञों की राय-डिजिटल ट्रैकिंग और थर्ड पार्टी ऑडिट जरूरी

पशुपालन क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि अब केवल विभागीय रिकॉर्ड पर्याप्त नहीं हैं,प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान को डिजिटल पोर्टल पर दर्ज किया जाए, पशु का टैग नंबर, पशुपालक का आधार सत्यापन,जीपीएस लोकेशन और जन्मे वत्स का फोटो रिकॉर्ड रखा जाए,साथ ही प्रत्येक वर्ष स्वतंत्र एजेंसी से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए,ताकि योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

यदि आरोप सही निकले तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

यदि जांच में यह सामने आता है कि कृत्रिम गर्भाधान और वत्स जन्म के आंकड़े वास्तविकता से मेल नहीं खाते,तो कई गंभीर प्रश्न स्वतः खड़े होंगे क्या केवल निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता जिम्मेदार होंगे? या फिर उन विभागीय अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी जिन्होंने बिना सत्यापन रिपोर्ट स्वीकार की? क्या सरकारी धन की वसूली होगी? क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय और आपराधिक कार्रवाई होगी?

अब इन सवालों के जवाब का इंतजार...

अब पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही हैं क्या एमसीबी जिले में कृत्रिम गर्भाधान और वत्स जन्म के सभी आंकड़ों का गांव-गांव जाकर स्वतंत्र भौतिक सत्यापन कराया जाएगा? क्या प्रत्येक विकासखंड की मासिक रिपोर्ट की निष्पक्ष जांच होगी? क्या इस योजना पर खर्च हुई सरकारी राशि का विशेष ऑडिट कराया जाएगा? क्या जांच में अनियमितताएं मिलने पर निजी कार्यकर्ताओं के साथ विभागीय अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी? और सबसे बड़ा सवाल—क्या शासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच कराएगा या यह मामला भी केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगा?

पुष्प,फल,छाया से परोपकार का संदेश: होली क्रॉस स्कूल में वन महोत्सव,50 पौधों का हुआ रोपण

आईएफएस अधिकारी प्रभाकर टोप्पो ने कहा-वृक्ष बचेंगे तभी बचेगा जीवन,विद्यार्थियों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

'पुष्पपत्रफलच्छाया, मूलवल्कल दारुभिः। धन्य महीरुहाः येषां, विमुखा यान्ति नार्थिनः।। '

अर्थात्–वे वृक्ष धन्य हैं,जो अपने फूल, पत्ते,फल,छाया,जड़,छाल और लकड़ी तक से दूसरों का उपकार करते हैं तथा जिनके द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता। इसी परोपकार और प्रकृति संरक्षण की भावना को आत्मसात करते हुए होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम),अंबिकापुर में शनिवार को वन महोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के इको क्लब एवं लिटरेरी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अभियान में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विद्यालय परिसर में लगभग 50 मौलसिरी के पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में कोरिया वनमंडल की वनमंडलाधिकारी एवं भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी श्रीमती प्रभाकर टोप्पो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सि. जेस्सी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण कर हरित भविष्य का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभाकर टोप्पो ने विद्यालय को लाल चंदन एवं दहिमन के पौधे भेंट किए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं,बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का आधार है। उन्होंने कहा कि यदि वन नहीं बचेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक असंतुलन मानव जीवन के लिए गंभीर संकट बन जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि लाल चंदन मुख्यतः कर्नाटक और पश्चिमी घाट में पाया जाता है,जबकि दहिमन बैकुंठपुर एवं मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र की औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु विलुप्तप्राय प्रजाति है। ऐसे पौधों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यालय की प्राचार्या डॉ. सि. जेस्सी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी से होती है। आज लगाए गए पौधे आने वाले वर्षों में विशाल वृक्ष बनकर विद्यालय को हरियाली,स्वच्छ वातावरण और शीतल छाया प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब ये पौधे विशाल वृक्ष बनेंगे,तब उनकी छांव में खेलने वाली नई पीढ़ी उन विद्यार्थियों को याद करेगी जिन्होंने आज इन्हें रोपा है। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने प्रकृति,वन एवं पर्यावरण की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया। पूरे आयोजन में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रही। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे पर्यावरण संरक्षण अभियान निरंतर चलाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

एनडीपीएस,एससी-एसटी एक्ट,साइबर क्राइम और फॉरेंसिक पर विवेचकों की कार्यशाला आयोजित...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। अपराधों की गुणवत्ता पूर्ण विवेचना और दोषसिद्धि दर में सुधार के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर में जिले के विवेचकों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में एनडीपीएस एक्ट,एससी-एसटी एक्ट, साइबर क्राइम एवं फॉरेंसिक से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का आयोजन डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशन में किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों, एसडीओपी (ग्रामीण) तुल सिंह पट्टावी, अतिरिक्त लोक अभियोजक नरेन्द्र पाण्डेय,नितेश चंद्र शुक्ला,मनोज तिवारी,एफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी तथा जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी एवं विवेचक उपस्थित रहे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने कहा कि अपराधों की प्रभावी विवेचना के लिए पारंपरिक साक्ष्यों के साथ डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का अधिकतम उपयोग आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक प्रकरण में तकनीकी साक्ष्यों को शामिल कर न्यायालय में मजबूत और प्रमाणिक केस प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक पदार्थों की पहचान, घटनास्थल की वीडियोग्राफी,टेस्टिंग किट के उपयोग,आर्थिक अनुसंधान तथा पीआईटी-एनडीपीएस के प्रावधानों की जानकारी दी गई। वहीं एससी-एसटी एक्ट के मामलों में त्वरित जांच, निष्पक्ष विवेचना और अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के पालन पर विशेष जोर दिया गया। साइबर अपराध से जुड़े मामलों में बैंक खातों की जानकारी तत्काल प्राप्त करने,अवैध निकासी रोकने,आईपी एड्रेस एवं मोबाइल संबंधी तकनीकी जानकारी जुटाने और आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की प्रक्रिया समझाई गई। फॉरेंसिक सत्र में विवेचकों को घटनास्थल सुरक्षित रखने, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रहण,पैकिंग,फिंगर प्रिंट संरक्षण तथा साक्ष्यों को दूषित होने से बचाने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

जमीन विवाद में युवक की हत्या,आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-

लखनपुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद और घर बनाने की बात को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गुस्से में मृतक के साथ लात-घूंसों से मारपीट की थी,जिससे गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, ग्राम तिरकेला निवासी धुंधुराम मझवार ने चौकी कुन्नी में सूचना दी थी कि उसके चचेरे भाई कामेश्वर मझवार को 26 जून को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां 27 जून को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मारपीट के कारण मौत होने की आशंका जताई थी।

मर्ग जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु हत्यात्मक पाए जाने के बाद पुलिस ने जांच तेज की। गवाहों के बयान में सामने आया कि घटना के दिन फुटकू मझवार ने जमीन और मकान निर्माण को लेकर हुए विवाद के दौरान कामेश्वर मझवार की लात-घूंसों से पिटाई की थी। मारपीट के बाद आरोपी घायल को अस्पताल तो ले गया, लेकिन इलाज कराने की बात कहकर वहां से फरार हो गया।

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै नन्द लाल यादव (माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री झउडी यादव गाँव/शहर पथरई, केसर पोस्ट-कमलेश्वरपुर तहसील-मैनपाट जिला -सरगुजा, छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र का नाम जीतेन्द्र यादव (Jitendra Yadav) से बदल कर बिरेन्द्र यादव (BIRENDRA YADAV) रख लिया है।

पालक

नन्द लाल यादव
पथरई, केसर तहसील-मैनपाट
जिला -सरगुजा, छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं अतनस किस्पोट्टा (ATNAS KISPOTTA) सुपुत्र अलोसियस किस्पोट्टा (Alosoous Kispotta) निवासी गाँव/शहर रामपुर बनवारी, आदर्शनगर, नजीबाबाद. तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) (वर्तमान निवासी छत्तीसगढ़) ने अपना नाम अतनस किसपोट्टा (ATNAS KISPOTTA) से बदल कर अथनस किस्पोट्टा (ATHANAS KISPOTTA) रख लिया है।

अथनस किस्पोट्टा
रामपुर बनवारी,आदर्शनगर,
नजीबाबाद. तहसील नजीबाबाद,
जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

नाम परिवर्तन सूचना

आमजन को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री बसंत कुमार मिश्रा, जेलपारा, जेलरोड, सूरजपुर, पोस्ट ऑफिस- सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ0ग0) पिन 497229 पंजीयन कं0 22202027200 दिनाँक 26.11.2020 मे एक नये भागीदार श्री आशुतोष मिश्रा पिता श्री राजेश मिश्रा, सुभाष वार्ड, देवरी, पोस्ट ऑफिस- देवरी, जिलाः सागर (म0प्र0) पिन 470226 दिनाँक 01.04.2026 को प्रवेश किये हैं एवं 1. श्री रमाकांत मिश्रा पिता स्व0 श्री हरगोविंद मिश्रा, 2. श्री कैलाश प्रसाद मिश्रा पिता स्व0 श्री हरगोविंद मिश्रा, 3. श्री प्रदीप मिश्रा पिता स्व0 श्री हरगोविंद मिश्रा एवं 4. श्रीमती सरोज मिश्रा पति श्री कैलाश प्रसाद मिश्रा सभी निवासी जेलपारा, जेलरोड, सूरजपुर, पोस्ट ऑफिसः सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ0ग0) पिन 497229 फर्म से अलग हो गये हैं। एक नये भागीदार का प्रवेश होना एवं चार (4) भागीदार का अलग होना समस्त भागीदारों के सहमती के आधार पर तय किया गया है।

श्री बसंत कुमार मिश्रा
भागीदार
मेसर्सः श्री बसंत कुमार मिश्रा
जेलपारा,जेलरोड, सूरजपुर,
जिला- सूरजपुर (छ0ग0)

CMYK

कथित प्रताड़ना,पुलिस को पहले से जानकारी और फिर आत्महत्या...आखिर जिम्मेदार कौन?

एक बेटी चली गई...लेकिन क्या उसे बचाया जा सकता था? बैकुंठपुर की घटना ने झकझोरा पूरा तंत्र

18 घंटे में क्या हुआ? नाबालिग की आत्महत्या ने पुलिस,परिवार और समाज तीनों को कटघरे में खड़ा किया

चोरी के आरोप से मौत तक... आखिर कहां चूक गई व्यवस्था?

क्या किसी ने उस बच्ची का दर्द समझा? बैकुंठपुर आत्महत्या प्रकरण में उठे कई अनुत्तरित सवाल

सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, आत्ममंथन भी जरूरी, नाबालिग की आत्महत्या ने पुलिसिंग और समाज दोनों को आईना दिखाया

एक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया...क्या समय रहते संवेदनशीलता दिखाई जाती तो बच सकती थी एक जान?

एफआईआर, कथित प्रताड़ना, 18 घंटे का अंतराल, कॉल डिटेल, पुलिस की भूमिका, डीजीपी के संदेश और अभिभावकों की जिम्मेदारी—हर पहलू की पड़ताल करती विशेष रिपोर्ट

-रवि सिंह-

कोरिया/बैकुंठपुर,11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आदिवासी नाबालिग छात्रा की आत्महत्या का मामला अब केवल एक आत्महत्या का मामला नहीं रह गया है,यह घटना समाज,पुलिस,अभिभावकों और पूरे प्रशासनिक तंत्र के सामने ऐसे प्रश्न छोड़ गई है जिनका उत्तर केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से नहीं मिलेगा,आज पूरे जिले में लोगों की एक ही मांग है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले,यह मांग पूरी तरह उचित भी है,लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर शायद सबसे कम चर्चा हो रही है क्या इस बच्ची को बचाया जा सकता था? यदि पूरे घटनाक्रम का समयक्रम देखा जाए तो उत्तर पूरी तरह असंभव नहीं लगता, संभव है कि'हाँ',यदि समय रहते संवेदनशीलता दिखाई जाती,उसकी मानसिक स्थिति को समझा जाता और परिस्थितियों को केवल लेन-देन या विवाद के रूप में नहीं देखा जाता।

चोरी के आरोप से शुरू हुआ घटनाक्रम, अगले दिन मौत में बदल गया

प्राप्त जानकारी और दर्ज एफआईआर के अनुसार 7 जुलाई की शाम बैकुंठपुर स्थित एक निजी आईसी मार्ट में किशोरी पर चोरी का आरोप लगाया गया,शिकायत के अनुसार उसे दुकान में रोका गया, उससे पूछताछ की गई और कथित रूप से मानसिक दबाव बनाया गया,एफआईआर में यह भी आरोप है कि उससे लिखवाया गया कि उसने चोरी की है तथा उसकी स्कूटी भी रोक ली गई,एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पहले लगभग 20 हजार रुपये और बाद में 50 हजार रुपये तक की राशि की मांग की गई, शिकायतकर्ता का कहना है कि राशि दिए बिना स्कूटी वापस नहीं करने की बात कही गई,इन आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्णय पुलिस विवेचना और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा,लेकिन इतना स्पष्ट है कि घटना के बाद किशोरी मानसिक दबाव में थी।

सूत्रों के अनुसार पुलिस को पहले ही थी... जानकारी,जांच में सीडीआर बन सकता है अहम साक्ष्य

विशेष सूत्रों के अनुसार कथित चोरी की घटना के बाद नाबालिग छात्रा ने स्वयं कोतवाली में पदस्थ एक एएसआई से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी,वहीं यह भी जानकारी सामने आ रही है कि दुकान संचालकों ने भी पुलिस को सूचना दी थी,इन तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि अभी जांच का विषय है,यदि जांच एजेंसियां मृतका द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल फोन का कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालती हैं,तो यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना से पहले और बाद में उसकी किन-किन लोगों से बातचीत हुई, उसने किसे फोन किया और किन लोगों ने उससे संपर्क किया,इसी प्रकार यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि 7 जुलाई को कथित चोरी की घटना सामने आने के बाद दुकान संचालकों ने सबसे पहले किस पुलिस अधिकारी या कर्मचारी से संपर्क किया था और उसके बाद पुलिस स्तर पर क्या कार्रवाई हुई,यदि इन पहलुओं की वैज्ञानिक जांच होती है तो घटनाक्रम की वास्तविक श्रृंखला स्पष्ट हो सकती है।

पुलिस की भूमिका पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका इसलिए चर्चा में है क्योंकि आरोप हैं कि विवाद की जानकारी पुलिस तक पहले ही पहुंच चुकी थी,यदि जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है कि पुलिस को जानकारी थी और दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई,तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा क्या उस समय नाबालिग की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को लेकर पर्याप्त संवेदनशीलता दिखाई गई? यह कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस हर आत्महत्या रोक सकती है,लेकिन यह अपेक्षा अवश्य की जाती है कि जब किसी नाबालिग से जुड़ा विवाद सामने आए, तो पुलिस केवल कानूनी पहलू ही नहीं बल्कि मानवीय पहलू को भी महत्व दे,यही कारण है कि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर चर्चा हो रही है,आज देशभर में बाल संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञ लगातार यह कहते हैं कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में कानूनी प्रक्रिया के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक सहयोग भी अनिवार्य होना चाहिए।

घटना के बाद पूरे 18 घंटे... लेकिन किसी ने बच्ची का मन नहीं पढ़ा?

जानकारी के अनुसार 7 जुलाई की शाम कथित चोरी की घटना सामने आई,अगले दिन लगभग 18 घंटे बाद नाबालिग ने आत्महत्या कर ली,यही 18 घंटे आज पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि इन 18 घंटों में परिवार को जानकारी थी,पुलिस तक भी विवाद की सूचना पहुंचने की बातें सामने आ रही हैं, दुकान संचालकों और परिवार के बीच बातचीत चल रही थी,समझौते के प्रयास भी किए जा रहे थे,लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है की क्या किसी ने उस बच्ची से पूछा कि वह मानसिक रूप से किस स्थिति में है? क्या किसी ने उससे कहा कि गलती हुई है तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती? क्या किसी ने यह समझने का प्रयास किया कि उसके मन में क्या चल रहा है? शायद नहीं...और यदि ऐसा नहीं हुआ तो यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी मानवीय विफलता मानी जाएगी।

कोरिया पुलिस के सामने लगातार उठते सवाल...

पिछले कुछ महीनों में कोरिया जिले में कई गंभीर घटनाओं के बाद पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न उठे हैं, पटना क्षेत्र 2023 की घटनाएं,नौगई तिहरा हत्याकांड,और अब यह आत्महत्या का मामला इन सभी घटनाओं के बाद लोगों के बीच यह चर्चा बढ़ी है कि क्या पुलिस समय रहते संभावित जोखिमों का आकलन करने में कहीं चूक रही है? यह कहना उचित नहीं होगा कि हर घटना के लिए पुलिस जिम्मेदार है,लेकिन यदि लगातार ऐसी घटनाओं के बाद समान प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, तो विभाग के भीतर आत्ममंथन आवश्यक हो जाता है।

यदि पुलिस को जानकारी थी तो क्या संवेदनशील हस्तक्षेप होना चाहिए था?

यह कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस हर आत्महत्या रोक सकती है,लेकिन जब किसी नाबालिग से जुड़ा गंभीर विवाद सामने आए और वह मानसिक दबाव में दिखाई दे,तब पुलिस की भूमिका केवल कानून तक सीमित नहीं रह जाती, ऐसे मामलों में संवेदनशील हस्तक्षेप भी पुलिसिंग का हिस्सा माना जाता है,यदि जांच में यह सामने आता है कि पुलिस को पहले से जानकारी थी, तो यह भी जांच का विषय होगा कि उस समय बच्ची की सुरक्षा और मानसिक स्थिति को लेकर क्या प्रयास किए गए।

क्या सिर्फ चोरी का आरोप ही वजह था?

जांच एजेंसियों को इस संभावना पर भी विचार करना होगा कि कहीं आत्महत्या के पीछे केवल कथित चोरी की घटना ही कारण नहीं थी,18 घंटे के दौरान क्या कोई और घटना हुई? क्या बच्ची किसी और मानसिक दबाव में थी? क्या उसने किसी से अपनी बात साझा करने की कोशिश की? इन सभी प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक जांच से ही सामने आएंगे।

दुकान संचालकों की भूमिका कानून तय करेगा...

एफआईआर में दुकान संचालकों पर कथित मानसिक प्रताड़ना,आर्थिक मांग और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं,इन आरोपों की सत्यता पुलिस विवेचना और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही तय होगी, इसलिए दोष तय करना न्यायालय का विषय है, लेकिन यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह निश्चित रूप से गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा।

डीजीपी का संदेश : बेहतर पुलिसिंग के लिए आत्मसमीक्षा और संवेदनशीलता जरूरी...

हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार को दिए गए साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरुण देव गौतम ने पुलिस व्यवस्था और समाज के संबंधों पर कई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें कहीं,उनका संदेश केवल पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ही नहीं,बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज और पुलिस एक-दूसरे के पूरक हैं,समाज की पुलिस से अपेक्षाएं हैं, वहीं पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वह संवेदनशील, जवाबदेह और जनविश्वास के अनुरूप कार्य करे,डीजीपी ने कहा कि सीमित संसाधनों और सीमित पुलिस बल के बावजूद बेहतर सोच,ईमानदारी और सकारात्मक नेतृत्व से प्रभावी पुलिसिंग की जा सकती है,उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को केवल आदेश देने तक सीमित न रहें,बल्कि उन्हें सही सोच और संवेदनशील कार्यशैली के लिए प्रेरित करें,उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हर बड़ी घटना को रोक पाना संभव नहीं होता,लेकिन जिन घटनाओं को समय रहते सतर्कता, दूरदृष्टि और संवेदनशील हस्तक्षेप से रोका जा सकता है,वहां किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए,प्रत्येक गंभीर घटना के बाद विभाग को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि चूक कहां हुई और भविष्य में उसे कैसे रोका जा सकता है, उनका पूरा संदेश यही था कि बेहतर पुलिसिंग का आधार केवल कानून नहीं, बल्कि संवेदनशीलता,आत्ममंथन,ईमानदारी और समाज के प्रति जवाबदेही है।

अभिभावकों के लिए भी बड़ा सबक...

यह घटना केवल पुलिस की नहीं,परिवार की भी जिम्मेदारी का संदेश देती है,आज अधिकांश अभिभावक बच्चों को अकेले खरीदारी के लिए भेज देते हैं,कम उम्र के बच्चों में परिस्थितियों को समझने और अचानक बने विवाद का सामना करने की क्षमता सीमित होती है,इसलिए विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि छोटे बच्चों को अकेले खरीदारी के लिए भेजने के बजाय अभिभावक स्वयं साथ जाएं,उन्हें सिखाएं कैसे खरीदारी की जाती है, कैसे भुगतान किया जाता है,किसी विवाद की स्थिति में क्या करना चाहिए,और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी परेशानी में तुरंत घरवालों को बताना चाहिए।

परिवारों के लिए भी बड़ा सबक...

इस घटना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष परिवार है,आज की पीढ़ी सोशल मीडिया, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबाव के बीच जी रही है, ऐसे समय में अभिभावकों की भूमिका केवल आर्थिक जरूरतें पूरी करना नहीं रह गई है,उन्हें बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना होगा,विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों से रोज बातचीत करें,उनकी भावनाओं को महत्व दें,गलती होने पर संवाद करें,केवल दंड नहीं,उन्हें यह भरोसा दें कि परिवार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा,कई बार केवल एक संवेदनशील बातचीत भी किसी की जान बचा सकती है।

पूर्व विधायक के सोशल मीडिया पोस्ट ने भी बढ़ाई चर्चा,पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे नए सवाल

आदिवासी नाबालिग छात्रा आत्महत्या प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश और कार्रवाई जारी है। इसी बीच पूर्व विधायक गुलाब कमरो का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा का विषय बन गया है,अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है 'कोरिया जिले को शर्मसार करने के बाद एसपी हटाए गए?' इस पोस्ट के बाद जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली और हाल के घटनाक्रम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पोस्ट केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हाल के दिनों में कोरिया जिले में हुई घटनाओं के संदर्भ में पुलिस व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को भी सामने लाता हैं, कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि यदि प्रारंभिक स्तर पर शिकायत मिलने के बाद अधिक संवेदनशीलता और प्रभावी हस्तक्षेप किया गया होता, तो संभवतः परिस्थितियां इतनी दुखद स्थिति तक नहीं पहुंचतीं, हालांकि, यह एक सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया है तथा मामले में वास्तविक जिम्मेदारी और तथ्यों का निर्धारण पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा, फिलहाल यह सोशल मीडिया पोस्ट भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है और पुलिस की कार्यशैली को लेकर चल रही बहस को और तेज कर रहा है।

जांच केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,जांच को यह भी स्पष्ट करना चाहिए...

- घटना के समय कौन-कौन मौजूद था?
- पुलिस को पहली सूचना कब मिली?
- क्या किसी अधिकारी ने नाबालिग से बातचीत की?
- क्या परिवार को उचित सलाह दी गई?
- क्या बाल संरक्षण से जुड़ी कोई प्रक्रिया अपनाई गई?
- क्या भविष्य के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने का कोई प्रोटोकॉल बनाया जा सकता है? यदि यह जांच इन प्रश्नों तक पहुंचेगी, तभी इस घटना से कोई सकारात्मक सीख निकलेगी।

दोष तय करना अदालत का काम, सीख लेना समाज का दायित्व

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एफआईआर में दर्ज आरोप शिकायतकर्ता के कथन पर आधारित हैं,आरोपियों का पक्ष सामने आना और न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर दोष तय करना अभी शेष है,इसलिए किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा,लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि एक 17 वर्षीय बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, और यह ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं।

समाज की भी जिम्मेदारी कम नहीं

यदि किसी किशोर पर आरोप लगता है, तो समाज का रवैया भी महत्वपूर्ण हो जाता है,आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी घटना पर तत्काल निर्णय,सार्वजनिक शर्मिंदगी और सामाजिक दबाव कई बार वास्तविक घटना से अधिक खतरनाक साबित हो जाते हैं,समाज को यह समझना होगा कि आरोप और अपराध सिद्ध होना दो अलग बातें हैं,विशेषकर नाबालिगों के मामलों में संवेदनशीलता सर्वोपरि होनी चाहिए।

एक बच्ची चली गई,अब कम से कम व्यवस्था जागे...

आज पूरा समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है,लोगों की मांग है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो,यह न्याय व्यवस्था का दायित्व है, लेकिन इस घटना का दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? यदि किसी नाबालिग के साथ विवाद हो,तो केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति का भी तत्काल आकलन हो, यदि पुलिस को किसी किशोर के गंभीर मानसिक तनाव की आशंका हो,तो काउंसलिंग और परिवार के साथ समन्वय की व्यवस्था बने,यदि समाज और परिवार समय रहते संवाद करें,तो शायद कई दुखद घटनाएं टाली जा सकती हैं,पूजा पैकरा अब लौटकर नहीं आएगी,लेकिन यदि उसकी मृत्यु से व्यवस्था,समाज और परिवार कोई सीख लेते हैं, तो शायद भविष्य में किसी और बेटी की जिंदगी बचाई जा सकेगी, यही इस दुःखद घटना से निकलने वाला सबसे बड़ा संदेश होना चाहिए।

CMYK

बीपीसीएल की जेसीबी बनी काल : युवक की मौत के बाद थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन,दो घंटे बाद पहुंचे थाना प्रभारी

सड़क पर मौत,थाने में धरना और देर से पहुंचे प्रभारी,बीपीसीएल परियोजना ने फिर खड़े किए बड़े सवाल

- बीपीसीएल की लापरवाही या सिस्टम की नाकामी ? जेसीबी हादसे में युवक की मौत, थाने के सामने शव रखकर न्याय की गुहार
- गैस लाइन से ज्यादा 'खतरे की लाइन'! बीपीसीएल की जेसीबी ने ली युवक की जान, प्रदर्शन के बीच पुलिस की तत्परता भी...
- विकास की कीमत या लापरवाही का परिणाम ? बीपीसीएल की जेसीबी से युवक की मौत, जनता सड़क पर...पुलिस दो घंटे बाद
- गलत दिशा से आ रही जेसीबी की टक्कर से एक युवक की मौत,दूसरा गंभीर,परिजनों ने एफआईआर,मुआवजे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

संवाददाता
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी),11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की गैस पाइपलाइन परियोजना के दौरान एक और दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया,पाइपलाइन कार्य में लगी एक जेसीबी की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, हादसे के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण 11 जुलाई को शव लेकर मनेंद्रगढ़ कोतवाली पहुंच गए और सुबह करीब 10 बजे से थाना परिसर के सामने धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन के दौरान एक और मुद्दा चर्चा का विषय बन गया,स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जब थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन चल रहा था, तब कोतवाली थाना प्रभारी लगभग दो घंटे बाद, दोपहर 12 बजे के बाद मौके पर पहुंचे,इसे लेकर पुलिस की तत्परता पर भी सवाल उठाए गए,वहीं बीपीसीएल की गैस पाइपलाइन परियोजना के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी,अधूरी सड़क मरम्मत और निर्माण कार्यों के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के आरोप भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। पूरे घटनाक्रम ने निर्माण एजेंसी की जवाबदेही के साथ-साथ पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन, एफआईआर और मुआवजे की मांग-11 जुलाई की सुबह मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शव लेकर मनेंद्रगढ़ कोतवाली पहुंचे,उन्होंने शव को थाने के सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया,प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी चालक को तत्काल गिरफ्तार किया जाए,बीपीसीएल कंपनी की जिम्मेदारी तय की जाए तथा मृतक के परिवार को उचित आर्थिक सहायता और न्याय दिया जाए।

धरना शुरू होने के दो घंटे बाद पहुंचे थाना प्रभारी,उठे सवाल-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई,स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सुबह लगभग 10 बजे से प्रदर्शन शुरू हो चुका था,लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी दोपहर लगभग 12 बजे के बाद मौके पर पहुंचे,प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब थाना परिसर के सामने शव रखकर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे,तब थाना प्रभारी की तत्काल उपस्थिति अपेक्षित थी, उनके विलंब से पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध जताया और इसे संवेदनशील मामलों में पुलिस की प्रतिक्रिया पर गंभीर प्रश्न बताया,सूत्रों के अनुसार यह भी चर्चा है कि थाना प्रभारी कथित रूप से मुख्यालय के बजाय चिरमिरी से आना-जाना करते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यदि ऐसा है, तो यह भी प्रश्न उठता है कि किसी आकस्मिक या कानून-व्यवस्था की स्थिति में त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया कैसे सुनिश्चित होगी, लगातार बातचीत और प्रशासन के आश्वासन के बाद लगभग ढाई बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ।

रेस्टोरेंट से घर लौटते समय हुआ हादसा

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना 10 जुलाई 2026 की रात लगभग 8:20 बजे की है,शिकायतकर्ता ने बताया कि वह अपने साथी राघवेंद्र और सागर के साथ पंकज रेस्टोरेंट में काम समाप्त कर घर लौट रहा था,राघवेंद्र स्कूटी चला रहा था और पीछे सागर बैठा था। दोनों जैसे ही आस्था रेस्टोरेंट के पास पहुंचे, सामने से कथित रूप से गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रही जेसीबी (क्रमांक MP-65-DA-0197) ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे।

एक युवक की मौके पर मौत, दूसरा अंबिकापुर रेफर

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने दोनों घायलों को तत्काल मनेंद्रगढ़ अस्पताल पहुंचाया,चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद राघवेंद्र को मृत घोषित कर दिया,जबकि गंभीर रूप से घायल सागर को बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया।

आरोपी चालक के खिलाफ अपराध दर्ज

पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी जेसीबी चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है,मामले की विवेचना जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बीपीसीएल की पाइपलाइन परियोजना पर फिर उठे सवाल

यह हादसा केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं माना जा रहा, बल्कि बीपीसीएल की गैस पाइपलाइन परियोजना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर रहा है,स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह-जगह सड़कें खोद दी गई हैं,लेकिन कई स्थानों पर मरम्मत अधूरी छोड़ दी गई है,सड़क किनारे भारी मशीनें संचालित होती हैं,पर पर्याप्त चेतावनी बोर्ड, बैरिकेडिंग और रात्रिकालीन सुरक्षा संकेत कई जगह दिखाई नहीं देते,लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाता, तो दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो सकती थी।

पूरे मामले में अब कई महत्वपूर्ण प्रश्न जांच का विषय हैं...

क्या जेसीबी वास्तव में गलत दिशा से संचालित हो रही थी? क्या चालक ने यातायात नियमों का उल्लंघन किया? क्या निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी? क्या बीपीसीएल परियोजना में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था? क्या पुलिस की प्रतिक्रिया समय पर और पर्याप्त थी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर पुलिस विवेचना और प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे, फिलहाल एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है, और पूरे घटनाक्रम ने विकास कार्यों में सुरक्षा, जवाबदेही और प्रशासनिक तत्परता तीनों पर गंभीर बहस छेड़ दी है।

स्वच्छ सूरजपुर,सुंदर सूरजपुर के संकल्प के साथ जनपद पंचायत प्रतापपुर में श्रमदान

-संवाददाता-
प्रतापपुर, 11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

'स्वच्छ सूरजपुर, सुंदर सूरजपुर' के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में जनपद पंचायत प्रतापपुर परिसर में स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता मो. जिशान खान,पत्रकार अशरफउल्लाह खान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अनिल कुमार तिवारी तथा जनपद पंचायत के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान कर स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत परिसर की साफ-सफाई के साथ-साथ पौधारोपण भी किया गया।

उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छ एवं हरित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सीईओ अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि स्वच्छता केवल शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने घर, मोहल्ले एवं सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने तथा समय-समय पर सामूहिक श्रमदान में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षित और जागरूक समाज की पहचान उसकी स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक सहभागिता से होती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प ले,तो पूरा जिला स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बन सकता है। उन्होंने जनहित के कार्यों में शासन एवं जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग करने का भी आह्वान किया। कार्यक्रम में लेखापाल परमानंद सिंह,अशोक सिंह, श्याम,अखिलेश कुशवाहा,जी.बी. राम,नीरज सिन्हा, प्रसाद धुर्वे,देवेंद्र सिंह, रूपा यादव,सतेन्द्र केरकेट्टा,प्रवीण सिंह, रहमत खान,सुनील पनेरिया, सुरजन सिंह, अनिल साहू सहित जनपद पंचायत के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सीईओ अनिल कुमार तिवारी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे स्वच्छता को केवल एक अभियान न मानें, बल्कि इसे अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का छोटा-सा प्रयास ही स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित सूरजपुर की मजबूत नींव बनेगा।

प्रतापपुर में नवनियुक्त एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

-संवाददाता-
प्रतापपुर, 11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

नगर पंचायत प्रतापपुर एवं नगर पंचायत जरही के नवनियुक्त एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को प्रतापपुर के मंगल भवन में आयोजित किया गया। समारोह में प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में एसडीएम ललिता भगत ने प्रतापपुर एवं जरही नगर पंचायत के नवनियुक्त एल्डरमैन लक्ष्मी गुप्ता, विजेंद्र कश्यप, बसराम सिंह, अरुण सिंह, रंजन सिंह एवं दीपक रजक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने नवनियुक्त एल्डरमैनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नगर पंचायतों के विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए क्षेत्र के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मानती सिंह, उपाध्यक्ष अजीत शरण सिंह, मंडल अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, पूरन रजवाड़े सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जंगल में कथित जुआ,गांव में चर्चा और पुलिस पर सवाल... आखिर सच क्या है?

तस्वीरों ने खोली कथित जुआ फड़ की परतें! परसगढ़ी-रापाखेरवा में बड़े खेल की चर्चा, पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल

- जंगल में कथित जुआ फड़ का खेल? तस्वीरें सामने आने के बाद जांच की मांग तेज
- परसगढ़ी-रापाखेरवा में कथित जुआ फड़ की चर्चा, तस्वीरों के बाद एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग
- तस्वीरों में दिखी भीड़ और नकदी,ग्रामीण बोले... जंगल में लंबे समय से चल रहा कथित जुआ फड़
- कथित जुआ फड़ पर तस्वीरों से मचा बवाल, ग्रामीणों ने उठाए पुलिस की सक्रियता पर सवाल
- जंगल में जुटती भीड़, लाखों के दांव की चर्चा... परसगढ़ी-रापाखेरवा के कथित जुआ फड़ की जांच कब?
- कथित जुआ फड़ का बड़ा खेल या सिर्फ अफवाह? तस्वीरों ने बढ़ाई हलचल,निष्पक्ष जांच की उठी मांग
- ग्रामीणों का दावा—सुनसान इलाके में नियमित जुटती है भीड़,तीन युवकों के संचालन की चर्चा
- तस्वीरों और शिकायतों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग, पुलिस की सक्रियता भी सवालों के घेरे में...

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़ (एमसीबी),11 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली क्षेत्र के परसगढ़ी और रापाखेरवा गांव इन दिनों कथित जुआ फड़ के संचालन को लेकर चर्चा में हैं, क्षेत्र से सामने आई कुछ तस्वीरों के बाद स्थानीय स्तर पर यह मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया है,तस्वीरों में जंगल के बीच बड़ी संख्या में लोग चादर बिछाकर बैठे दिखाई दे रहे हैं,कुछ लोगों के हाथों में नकदी जैसी वस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर स्थानीय ग्रामीण दावा कर रहे हैं कि यहां लंबे समय से बड़े स्तर पर कथित जुए का फड़ संचालित हो रहा है, हालांकि,केवल तस्वीरों के आधार पर किसी भी व्यक्ति या गतिविधि को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता,इन दावों की पुष्टि सक्षम जांच के बाद ही संभव है, इसके बावजूद स्थानीय लोगों की शिकायतों ने पुलिस की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों का दावा—सुनसान जंगलों में नियमित रूप से जुटती है भीड़-स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि परसगढ़ी और रापाखेरवा के आसपास स्थित सुनसान इलाकों में नियमित रूप से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं,उनका आरोप है कि यहां हजारों से लेकर लाखों रुपये तक के दांव लगाए जाते हैं और यह गतिविधि कोई नई नहीं बल्कि लंबे समय से चल रही है,ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह केवल सामान्य बैठक होती तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों की आवाजाही लगातार नहीं होती। उनका आरोप है कि इस गतिविधि से आसपास के गांवों का सामाजिक माहौल भी प्रभावित हो रहा है।

तीन युवकों के संचालन का दावा,लेकिन जांच के बाद ही होगी पुष्टि

सूत्रों के अनुसार,स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि कथित जुआ फड़ का संचालन मुकेश यादव,रवि और आकाश नामक तीन युवक करते हैं,हालांकि,इस संबंध में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही किसी के विरुद्ध इस मामले में अपराध दर्ज होने की जानकारी सामने आई है,ऐसे में इन नामों का उल्लेख केवल स्थानीय दावों और सूत्रों के आधार पर है, इनकी सत्यता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

सबसे बड़ा सवाल—क्या स्थानीय पुलिस को नहीं थी जानकारी?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न स्थानीय पुलिस की सक्रियता को लेकर उठ रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि यदि जंगलों में नियमित रूप से दर्जनों वाहन पहुंचते हैं, घंटों तक भीड़ जुटती है और कथित रूप से बड़े पैमाने पर लेन-देन होता है,तो क्या इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को नहीं हो सकती? लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को जानकारी नहीं थी, तो यह निगरानी व्यवस्था पर प्रश्न है, और यदि जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई—यह भी जांच का विषय है।

जुए से बर्बाद हो रहे परिवार,ग्रामीणों ने जताई चिंता

ग्रामीणों का कहना है कि कथित जुए की वजह से कई परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं,उनका आरोप है कि गांवों के युवा तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहे हैं,जिससे मेहनत की कमाई दांव पर लग रही है,इससे सामाजिक तनाव और पारिवारिक विवाद भी बढ़ने की आशंका है,लोगों का मानना है कि यदि समय रहते ऐसी गतिविधियों पर रोक नहीं लगी,तो इसका असर आने वाले समय में कानून-व्यवस्था और सामाजिक माहौल पर भी पड़ सकता है।

तस्वीरें बनीं चर्चा का आधार, लेकिन निष्पक्ष जांच जरूरी

सामने आई तस्वीरों ने निश्चित रूप से कई सवाल खड़े किए हैं,लेकिन केवल तस्वीरों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा,यह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इन तस्वीरों, स्थानीय शिकायतों और उपलब्ध तथ्यों की निष्पक्ष जांच करें,यदि जांच में यह सामने आता है कि वास्तव में वहां अवैध जुआ संचालित हो रहा था,तो संबंधित संचालकों के साथ-साथ यदि किसी स्तर पर संरक्षण मिला हो, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।

ग्रामीणों की मांग—एसपी स्तर से हो जांच

क्षेत्र के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है,उनका कहना है कि यदि परसगढ़ी और रापाखेरवा में कथित जुआ फड़ का संचालन हो रहा है,तो इसके पीछे काम कर रहे लोगों और यदि किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है तो उसकी भी जांच की जाए, लोगों का कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई से ही जनता का पुलिस पर विश्वास मजबूत होगा और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लग सकेगी।

अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर...

फिलहाल पूरा मामला स्थानीय लोगों के आरोपों, सामने आई तस्वीरों और सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है, अब यह पुलिस की जांच पर निर्भर करेगा कि तस्वीरों और शिकायतों में कितनी सच्चाई है, यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह न केवल कथित संचालकों पर कार्रवाई का आधार बनेगा, बल्कि स्थानीय निगरानी व्यवस्था और पुलिस की सक्रियता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करेगा।

CMYK

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज का वो हिट गाना,आज भी यादगार

बॉलीवुड में कई ऐसे गाने आए हैं,जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों को यादगार बनाया बल्कि कलाकारों की पहचान को भी नई ऊंचाई दी। ऐसा ही एक गाना 33 साल पहले रिलीज हुई फिल्म खलनायक का है,जो आज भी लोगों की जुबान पर बना हुआ है। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसकी गूंज ऑटो रिक्शा से लेकर गलियों और चौराहों तक सुनाई देती थी। हम बात कर रहे हैं साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक के मशहूर गाने नायक नहीं खलनायक हूं मैं की। इस गाने ने फिल्म के साथ-साथ अभिनेता संजय दत्त की छवि को भी एक अलग पहचान दी। गाने की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी कि यह उस दौर के सबसे चर्चित गीतों में शामिल हो गया था।

फिल्म खलनायक में संजय दत्त के साथ माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म का निर्देशन सुभाष घई ने किया था और यह बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करने वाली फिल्मों में शामिल रही। फिल्म की कहानी,कलाकारों की अदाकारी और इसके

गानों ने दर्शकों के बीच खास जगह बनाई। नायक नहीं खलनायक हूं मैं गाने ने संजय दत्त के किरदार बल्लू बलराम को दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था। इस गाने के बाद संजय दत्त की बैड ब्वॉय इमेज को भी काफी मजबूती मिली। उनका अंदाज, डांस स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी पसंद आया।

इस गाने को मशहूर गायिका कविता कृष्णमूर्ति और विनोद राठौड़ ने अपनी आवाज दी थी। वहीं इसके बोल दिग्गज गीतकार आनंद बक्शी ने लिखे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी ने इस गाने को यादगार धुन दी थी। गाने के बोल और संगीत का ऐसा मेल बना कि यह लंबे समय तक लोगों की पसंद बना रहा।

90 के दशक में फिल्मी गानों का असर लोगों की जिंदगी पर काफी ज्यादा होता था। उस समय टीवी चैनलों,कैसेट्स और रेडियो के जरिए गाने लोगों तक पहुंचते थे। नायक नहीं खलनायक हूं मैं भी ऐसा ही गीत था,जिसे हर उम्र के लोगों ने पसंद किया। शादी समारोहों,पार्टियों और सार्वजनिक जगहों पर यह गाना खूब बजता था।

संजय दत्त के करियर में भी यह फिल्म और यह गाना बेहद खास माना जाता है। खलनायक ने उन्हें एक अलग तरह की पहचान दिलाई। उनके किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज भी जब संजय दत्त की फिल्मों की चर्चा होती है तो खलनायक का नाम जरूर लिया जाता है। समय बदल गया,संगीत के तरीके बदल गए और नई पीढ़ी के कलाकारों के नए गाने आने लगे,लेकिन नायक नहीं खलनायक हूं मैं की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। यही वजह है कि इसे 90 के दशक के उन चुनिंदा गानों में गिना जाता है,जो अपनी धुन,बोल और कलाकारों की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे।

सिल्क साड़ी में जाह्नवी कपूर ने बिखेरा जलवा, ट्रेडिशनल आउटफिट में लगाया बोल्डनेस का तड़का

बॉलीवुड की यंग और खूबसूरत एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर अपने बेहतरीन फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं।इन लेटेस्ट तस्वीरों में जाह्नवी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने भारतीय परंपरा को बोल्डनेस के साथ पेश किया है। तस्वीरों में जाह्नवी कपूर ने एक बेहद खूबसूरत लैवेंडर और गोल्डन शेड वाली सिल्क साड़ी पहनी हुई है। साड़ी का बॉर्डर काफी हैवी है, जो इसे बेहद रॉयल लुक दे रहा है। साड़ी के साथ जाह्नवी ने मैचिंग स्ट्रैपलेस स्टाइल ब्लाउज कैरी किया है, जो उनके इस एथनिक लुक में मॉडर्न और ग्लैमरस टच जोड़ रहा है।तस्वीरों में जाह्नवी एक से बढ़कर एक सेक्सी और अट्रैक्टिव पोज देते नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। उनके इन बोल्ड पोज ने ट्रेडिशनल लुक में भी हॉटनेस का तड़का लगा दिया है।जाह्नवी ने न्यूड-ग्लॉसी लिपस्टिक,सटल मेकअप, विंग्ड आईलाइनर और माथे पर एक छोटी सी बिंदी के साथ अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारा है।

इस रॉयल लुक को पूरा करने के लिए जाह्नवी ने अपने बालों का एक नीट और क्लीन स्लीक जूड़ा बनाया हुआ है, जिसे पारंपरिक हेयर एक्सेसरीज से सजाया गया है।ज्वेलरी की बात करें तो उन्होंने गले में एक बेहद हैवी कुंदन और पर्ल का चोकर नेकलेस,मैचिंग झुमके,हाथों में ढेर सारी खूबसूरत चूड़ियां, बाजूबंद और अंगूठियां पहनी हुई हैं,जो उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

आदित्य रॉय कपूर की नई फिल्म का ऐलान

मिलाप मिलन जावेरी संग पहली बार करेंगे काम

आशिकी 2,मलंग और मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्मों से अपनी रोमांटिक छवि बनाने वाले अभिनेता आदित्य रॉय कपूर अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर खास लव स्टोरी लेकर आने वाले हैं। इस बार वह पहली बार निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी के साथ हाथ मिला रहे हैं। दोनों की यह फिल्म रोमांस, एक्शन और संगीत का दमदार मेल होगी, जिसे निर्माता भूषण कुमार बड़े स्तर पर बना रहे हैं। निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी ने आदित्य रॉय कपूर के साथ अपनी पहली फिल्म को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा,आदित्य प्यार को बेहद गहराई के साथ पर्दे पर उतारते हैं। आशिकी 2 के बाद से दर्शकों ने उन्हें जुनून और टूटे दिल की कहानियों में खूब पसंद किया है। इस नई फिल्म का किरदार कई परतों वाला होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सफर को उनसे बेहतर कोई और निभा सकता था। वहीं,निर्माता भूषण कुमार ने आदित्य के साथ अपनी पुरानी साझेदारी को याद करते हुए कहा,आदित्य के साथ हमारा रिश्ता कई सालों पुराना है और हमने साथ मिलकर ऐसी फिल्में दी हैं जिन्हें दर्शक आज भी पसंद करते हैं। आशिकी 2 से लेकर मेट्रो इन दिनों तक हर फिल्म हमारे लिए खास रही है। हमारे बीच शानदार क्रिएटिव तालमेल है और मुझे खुशी है कि हम एक बार फिर एक ऐसी कहानी के लिए साथ आ रहे हैं,जो भावनात्मक और बड़े

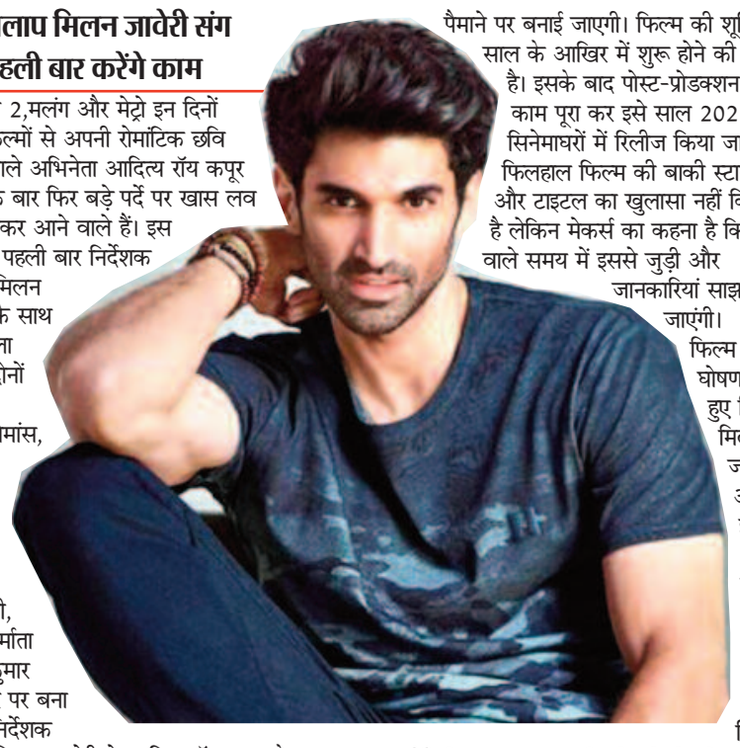

पैमाने पर बनाई जाएगी। फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में शुरू होने की तैयारी है। इसके बाद पोस्ट-प्रोडक्शन का काम पूरा कर इसे साल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल फिल्म की बाकी स्टारकास्ट और टाइटल का खुलासा नहीं किया गया है लेकिन मेकर्स का कहना है कि आने वाले समय में इससे जुड़ी और जानकारियां साझा की जाएंगी।

फिल्म की घोषणा करते हुए मिलाप मिलन जावेरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक खास पोस्ट साझा किया था। उन्होंने लिखा,इस बार आशिकी पूरी दीवानियत से होगी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर रहा हूं। यह एक इंटेंस, हिंसक और म्यूजिकल लव स्टोरी है, जिसमें मेरे प्रिय मित्र और शानदार अभिनेता आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

उन्होंने आगे लिखा,आदित्य को उनके करियर के सबसे दमदार, रोमांटिक और हीरोइक किरदारों में से एक में देखने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे खुशी है कि यह फिल्म भूषण कुमार सर के बैनर तले बन रही है, जिनके साथ मैंने सत्यमेव जयते और मरजावां जैसी सफल फिल्मों में काम किया है।

उन्होंने पोस्ट के आखिर में लिखा, 2027 में सिनेमाघरों में मिलते हैं,जहां एक्शन, संगीत, दमदार डायलॉग,रोमांस,जुनून और दिल टूटने का दर्द- सब कुछ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा।

सहेली आकांशा रंजन कपूर की प्री-वेडिंग में आलिया भट्ट ने लगाए जमकर ठुमके

आकांशा रंजन कपूर प्री-वेडिंगः एक्ट्रेस आकांशा रंजन कपूर की प्री-वेडिंग सेरेमनी से आलिया भट्ट का वीडियो वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आकांशा रंजन कपूर अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। एक्ट्रेस की शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं। आकांशा की प्री-वेडिंग सेरेमनी में चार-चांद लगाने उनकी बचपन की दोस्त आलिया भट्ट भी पहुंचीं। मुंबई में आकांशा रंजन की ग्रैंड प्री-वेडिंग पार्टी होस्ट हुई। इस सेरेमनी में बी-टाउन के बड़े-बड़े सितारों ने शिरकत की। ऐसे में आलिया भट्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में कैसे न आतीं।

सहेली के फंक्शन में बन-ठन कर पहुंची आलिया

बचपन की सहेली आकांशा के प्री-वेडिंग फंक्शन में आलिया भट्ट बन-ठनकर पहुंचीं। इस फंक्शन में एक्ट्रेस ने स्टाइलिश साड़ी पहनी थी। उन्होंने प्री-ड्रैप्ड स्टेटमेंट सिल्क साड़ी कैरी की जिसे उन्होंने स्ट्रैपलेस ब्लाउज से स्टाइल किया। उन्होंने चोकर, स्लीक बन और न्यूड मेकअप से अपने ओवरऑल लुक को क्लासिक बनाया।

प्री-वेडिंग में एक्ट्रेस ने दी परफॉर्मेंस

आकांशा रंजन कपूर की प्री-वेडिंग सेरेमनी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आलिया भट्ट शाह रुख खान की फिल्म कल हो ना हो के गाने माही वे पर लटके-झटके मार रही हैं। उनके साथ आकांशा की बहन और बाकी दोस्त भी डांस कर रहे हैं। सहेली की शादी में आलिया ने महफिल जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

आकांशा रंजन की प्री-वेडिंग में आलिया भट्ट के अलावा जाह्नवी कपूर, अर्जुन कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे थे।

किससे शादी कर रहीं आकांशा?

आज यानी 11 जुलाई को आकांशा फिल्ममेकर शरण शर्मा के साथ शादी रचा रही हैं। 12 जुलाई को मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन वेडिंग फंक्शन भी होस्ट होगा। कपल करीब 4 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहा है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो आकांशा हाल ही में ग्राम चिकित्सालय के दूसरे सीजन में नजर आई थीं। उन्हें पहले सीजन के लिए भी खूब प्यार मिला था। वह गिल्टी, मोनिका ओह माय डार्लिंग और जिगरा में भी काम कर चुकी हैं।

दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा से रिलीज हुआ नया गाना धीरे धीरे, फहीम अब्दुल्ला और शिल्पा राव ने दी आवाज

दिलजीत दोसांझ की फिल्म मैं वापस आऊंगा पिछले महीने 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 27 दिन बाद भी यह बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है और इसने दुनियाभर में करीब 90.37 करोड़ रुपये की ताजा कमाई कर ली है। फिल्म में शरवरी वाघ,वेदांग रैना और नसीरुद्दीन शाह भी मौजूद हैं। निर्माताओं ने फिल्म से एक नया गाना धीरे धीरे जारी किया है,जो अब यूट्यूब पर मौजूद है। इसका फिल्मांकन फिल्म के सभी कलाकारों पर हुआ है।इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म में,नसीरुद्दीन ऐसे किरदार में हैं जो भारत विभाजन के कारण अपनी प्रेमिका से दूर हो गए थे। इस गम में उनकी याददाश्त चली गई। धीरे धीरे गाना उनके इसी संघर्ष और खोई यादों को दर्शाता है,जिसे फहीम अब्दुल्ला और शिल्पा राव ने आवाज दी है। इसमें उनका साथ अंतरा नंदी और हीर ने दिया है। गाने के भावुक बोल इरशाद कामिल ने लिखे हैं,जबकि एआर रहमान का संगीत है।

खेल समाचार

हरमनप्रीत कौर 9,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं

नईदिल्ली,11 जुलाई 2026। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ जारी एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान हासिल की। उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ 13 रनों की जरूरत थी और उन्होंने भारत की पारी के 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर यह उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने कुल 58 रन बनाए।

हरमनप्रीत के अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 7 मार्च,2009 को बोवरल में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे मैच से की थी। वह मिताली राज (10,868) और स्मृति मंधाना (10,600 से अधिक) के बाद महिला

क्रिकेट में 9,000 रन बनाने वाली तीसरी भारतीय क्रिकेटर हैं। शुक्रवार को 121 गेंदों पर खेली गई 58 रनों की पारी में उन्होंने सात चौके लगाए और मंधाना (83) के साथ चौथे विकेट के लिए 155 गेंदों पर 89 रनों की साझेदारी निभाई।

हरमनप्रीत महिला क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं,जिन्होंने 164 वनडे मैचों में 37.22 की औसत से 4,541 रन और 202 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 30.33 की औसत से 4,216 रन बनाए हैं। उन्होंने 8 टेस्ट मैचों में 26.18 की औसत से कुल 288 रन भी बनाए हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके नाम 8 शतक और 44 अर्धशतक हैं। हरमनप्रीत 200 से अधिक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली और एकमात्र खिलाड़ी (पुरुष या महिला) हैं।

असम क्रिकेट एसोसिएशन ने पहले असम प्रीमियर लीग ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों के पूल की घोषणा की

गुवाहाटी,11 जुलाई 2026। असम क्रिकेट एसोसिएशन ने असम प्रीमियर लीग के पहले सीज़न के लिए खिलाड़ियों के पूल की घोषणा की है। लीग में भाग लेने के इच्छुक रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में से कुल 275 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एक विज्ञप्ति के अनुसार,इस पूल में 20 मार्की खिलाड़ी और सामान्य श्रेणी में 250 से अधिक खिलाड़ी शामिल हैं। पहले सीज़न के लिए अपनी टीमें बनाने के लिए फ्रेंचाइजी की बोली के दौरान इन सभी खिलाड़ियों की नीलामी (ऑक्शन) होगी। मार्की खिलाड़ियों की सूची असम के सीनियर घरेलू खिलाडियों में से तैयार की गई है। डेनिश दास,सिबशंकर रॉय,सुमित कश्यप, स्वरूपम पुरकायस्थ और जितुमोनी कलिता बल्लेबाजी और ऑल-राउंडर विकल्पों में प्रमुख हैं,जबकि मृण्मय दत्ता,मुख्तार हुसैन,अभिनव चौधरी,राहुल सिंह,सड़क हुसैन और भार्गव प्रतिम लखर गेंदबाजी समूह का नेतृत्व करते हैं। साहिल जैन, प्रद्युन सैकिया और सौरव मौसम डिहिंगिया बल्लेबाजी पूल को मजबूती देते हैं; अब्दुल अजीज कुरैशी,आकाश सेनगुप्ता और आयुष्मान मलाकार ऑल-राउंडर क्षमता लाते हैं; और सुमित घडिगांवकर,रोहित सेन और रुहिनंदन पेगु

विकेटकीपिंग के विकल्प हैं। ये सभी 20 खिलाड़ी असम के लिए बीसीसीआई टूर्नामेंट खेल चुके हैं और उम्मीद है कि नीलामी के दिन इन पर सबसे बड़ी बोली लगेगी। आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी 19 जुलाई, 2026 को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में होगी,जहां भाग लेने वाली फ्रेंचाइजी पहले सीज़न के लिए अपनी-अपनी टीमें बनाने के लिए खिलाड़ियों का चयन करेंगी। यह लीग असम के क्रिकेटरों को चयनकर्ताओं के सामने अपना हुनर दिखाने का मंच देगी और इससे आगामी बीसीसीआई घरेलू सीज़न के लिए खिलाड़ियों की पहचान और चयन में सीधे मदद मिलेगी।

एशियन गेम्स से पहले कोच मैरिजने का संदेश,टीम लक्ष्य पर दें ध्यान

बैंगलुरू,11 जुलाई 2026। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच स्योर्ड मारिजने ने अपनी खिलाड़ियों से कहा है कि वे 20 वें एशियाई खेल (आइची-नागोया 2026) की तैयारी करते समय अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बजाय टीम के लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। ये खेल जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने हैं। हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को आगामी एशियाई खेलों के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे टीम की कप्तानी जारी रखेंगी; उन्होंने पिछले महीने न्यूजीलैंड में टीम को नेशंस कप में जीत दिलाई थी। टीम की घोषणा के बाद बात करते हुए,कोच मारिजने ने खिलाडियों से अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बजाय टीम के लक्ष्यों को

प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामूहिक सफलता से स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत उपलब्धियां भी हासिल होंगी। उन्होंने कहा कि इस सोच से हाल के महीनों में टीम को फायदा हुआ है और वह इस बात पर लगातार जोर देते रहे हैं।

उन्होंने कहा,खिलाड़ियों के लिए एक सलाह यह है कि वे अपने काम पर ध्यान दें और उसे जितना हो सके उतना बेहतर ढंग से करें। साथ ही, अपने व्यक्तिगत लक्ष्य के बजाय टीम के लक्ष्य पर ध्यान दें,क्योंकि अगर आप टीम के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। पिछले कुछ महीनों में यह बहुत सकारात्मक और अच्छा रहा है, और मैं उन्हें इस बात की याद दिलाता रहता हूं।

स्कालोनी ने की मेसी की जमकर तारीफ

टेक्सास,11 जुलाई 2026। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कालोनी ने फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के लगातार अच्छे प्रदर्शन की तारीफ़ करते हुए कहा कि हर मैच में उनका खेल ऊंचे स्तर का रहता है।उन्होंने कहा कि भले ही मेसी ने अपने फिटनेस कोच के साथ काम करके अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार किया है, लेकिन सबसे बड़ा फ़र्क मैदान पर उनके कमिटमेंट का है। स्कालोनी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जब मेसी अपना सब कुछ झोंक देते हैं और उन्हें असर डालने का मौका दिखता है,तो वे एक मशीन बन जाते हैं। रॉयटर्स के अनुसार, स्कालोनी ने कहा,लियो हर मैच में लगभग एक जैसा ही दौड़ते हैं। शारीरिक रूप से, यह सच है कि उन्होंने अपने फिटनेस कोच के साथ तैयारी की है और इसका फ़ायदा भी मिला है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से, मुझे नहीं पता कि उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है या नहीं। कोच ने आगे कहा,मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होती। साफ़ बात यह है कि वे अपना सब कुछ दे रहे हैं। जब वे अपना सब कुछ देते हैं और उन्हें लगता है कि वे ख़तरा पैदा कर सकते हैं,तो वे एक मशीन बन जाते हैं।स्कालोनी ने मेसी की उम्र को लेकर उठने वाले सवालों को खारिज करते हुए कहा कि जो लोग उन्हें नहीं जानते, उन्हें 39 साल की उम्र में उनके खेल के स्तर को देखकर हैरानी हो सकती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जब तक मेसी खेलना जारी रखेंगे,वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी यह राय मेसी की काबिलियत पर आधारित है,न कि कोच के तौर पर उनकी भूमिका पर। हो सकता है कि जो लोग उन्हें नहीं जानते, उन्हें उम्मीद रही हो कि 39 साल की उम्र में वे इस स्तर पर नहीं होंगे,लेकिन मैंने न जाने कितनी बार कहा है: जब तक वे चाहें,वे सर्वश्रेष्ठ बने रहेंगे। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूं,न कि इसलिए कि मैं उनका कोच हूं। स्कालोनी ने स्विस टीम की तारीफ़ की,क्योंकि उन्होंने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 72 साल में पहली बार क्वार्टर फ़ाइनल में जगह बनाई है ।

CMYK

प्रसिद्ध मिठाई दुकान में भीषण आग लाखों का सामान जलकर राख

तखतपुर,11 जुलाई 2026। तखतपुर के प्रसिद्ध श्री गणेश कॉफी एंड स्वीट्स में भीषण आग लगने से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका।

प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह रहा कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग सब कुछ तबाह कर चुकी थी। होटल का फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री जलकर राख हो चुके थे, जिससे सालों की कमाई कुछ मिनटों में बरबाद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर तखतपुर में स्थायी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। गौरतलब है कि करीब दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री ने तखतपुर में फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी। हर आगजनी की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की कमी का मुद्दा उठता है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। घटना के बाद लोगों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि आग जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और प्रशासन की सुस्त कार्यशैली का खामियाजा आम नागरिकों को बार-बार भुगतना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री सांय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त....

आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन रही है महतारी वंदन योजना : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,11 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि

आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ श्लखपति दीदीश् जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।

बीएससी नर्सिंग प्रवेश में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल नियम रद्द...

बिलासपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के बीएससी (नर्सिंग) प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता को अवैध घोषित कर निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) द्वारा न्यूनतम परसेंटाइल की शर्त में छूट दिए जाने के बाद राज्य सरकार अपनी ओर से नई पात्रता शर्त लागू नहीं कर सकती। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर नई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर सभी रिक्त सीटों पर केवल प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएं। हाईकोर्ट ने अपने 52 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में कहा कि नर्सिंग शिक्षा के मानक तय करने का अधिकार केवल भारतीय नर्सिंग परिषद को है। यदि परिषद किसी विशेष परिस्थिति में प्रवेश नियमों में छूट प्रदान करती है तो राज्य सरकार या चिकित्सा शिक्षा विभाग उसमें संशोधन या अतिरिक्त शर्त नहीं जोड़ सकते। राज्य सरकार केवल परिषद के नियमों को लागू करने वाली एजेंसी है और उसे निर्धारित दायरे में ही कार्य करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने बताया गया कि

प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की कुल 7,811 स्वीकृत सीटें हैं। पहले चरण की काउंसलिंग के बाद 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रहने पर राज्य सरकार ने स्वयं भारतीय नर्सिंग परिषद से न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता में छूट देने का अनुरोध किया था। परिषद ने राज्य सरकार के अनुरोध पर 29 दिसंबर 2025 को यह छूट प्रदान कर दी थी ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिल सके और सीटें खाली न रहें। हालांकि परिषद से छूट मिलने के बावजूद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पूरी राहत लागू करने के बजाय 10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल की नई शर्त जोड़ दी। इस अतिरिक्त पात्रता नियम के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए और छूट मिलने के बाद भी दो हजार से अधिक सीटें खाली रह गईं। इस निर्णय से विशेष रूप से दूरस्थ, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के ऐसे छात्र-छात्राओं को नुकसान हुआ जिन्होंने प्रवेश परीक्षा तो दी थी, लेकिन नई परसेंटाइल शर्त के कारण उन्हें प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार का यह निर्णय भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा दी गई छूट की मूल भावना के विपरीत था। परिषद का उद्देश्य खाली सीटों को भरना और योग्य अभ्यर्थियों को अवसर उपलब्ध कराना था, जबकि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त शर्त लगाए जाने से वही उद्देश्य प्रभावित हो गया। अदालत ने माना कि इस प्रकार की नई पात्रता शर्त लागू करना अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्रवाई है। इस मामले में प्रभावित विद्यार्थियों और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि परिषद द्वारा पूर्ण छूट दिए जाने के बाद भी राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से नया नियम लागू कर दिया, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ और कई कॉलेजों की सीटें भी खाली रह गईं।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवविज्ञान विषयों के साथ 12वीं उत्तीर्ण तथा कॉमन एंट्रेंस परीक्षा में शामिल सभी पात्र अभ्यर्थियों को केवल प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश का अवसर दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत न्यूनतम परसेंटाइल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर नई काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी रिक्त सीटों पर पारदर्शी तरीके से मेरिट के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित किया जाए।

मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी...रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की बढ़ी सीट

रायपुर,11 जुलाई 2026। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटों को बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। अब कॉलेज में कुल सीटों की संख्या 230 से बढ़कर 250 हो गई है। यानी इस साल 20 और छात्र अपनी डॉक्टर बनने की राह को आसान कर सकेंगे।

एनएमसी के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने 10 जुलाई को इस संबंध में ऑफिशियल लेटर जारी किया है। यह नई सीटें शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगी। कॉलेज प्रबंधन ने इस फैसले का स्वागत किया है और छात्रों के लिए कैंपस में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। रायपुर के इस सबसे पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज का इतिहास काफी लंबा है। साल 1963 में जब इसकी शुरुआत हुई थी,तब सिर्फ 60 सीटें हुआ करती थीं। समय के साथ सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ। साल 2009 में ये 150 हुईं, फिर 2019 में 180 और 2023 में 230 सीटें हुईं। अब एनएमसी की नई इजाजत के बाद यह संख्या 250 तक पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्री ने जताया आभार

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस फैसले को राज्य के युवाओं के लिए बड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि सीटें बढ़ने से छत्तीसगढ़ के ज्यादा छात्र अब अपने ही राज्य में रहकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय के प्रयासों की भी सराहना की गई है। जानकारों का मानना है कि इससे राज्य में भविष्य में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।

343 कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों को राहत अब दिन के हिसाब से मिलेगा मानदेय

रायपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों अतिथि व्याख्याताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। लंबे समय से चली आ रही 'पीरियड आधारित' मानदेय प्रणाली के कारण उत्पन्न विवादों और असंतोष को समाप्त करते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक अतिथि व्याख्याताओं को उनके द्वारा पढ़ाए गए पीरियड की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता था, जिसे बदलकर अब 'दैनिक मानदेय' प्रणाली लागू की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस नई व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं,जिससे अब शिक्षकों को उनकी मेहनत का उचित और निश्चित प्रतिफल प्राप्त होगा। नई प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, अतिथि व्याख्याताओं को अब प्रति पीरियड के बजाय एक निश्चित दैनिक मानदेय दिया जाएगा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, एक अतिथि व्याख्याता को अब प्रति दिन 2,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही, एक महीने में अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा 50,000 रुपये निर्धारित की गई है। यह बदलाव उन व्याख्याताओं के लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगा, जो अब तक कॉलेज प्रबंधन द्वारा कम पीरियड आवंटित किए जाने के कारण आर्थिक तंगी का सामना

कर रहे थे। इस नई नीति से न केवल उनकी आय में स्थिरता आएगी, बल्कि उनके कार्य करने के तौर-तरीकों में भी पारदर्शिता आएगी। वर्तमान प्रणाली में अतिथि व्याख्याताओं को 40-45 मिनट के पीरियड के लिए 400 रुपये और 60 मिनट के पीरियड के लिए 500 रुपये का भुगतान किया जाता था। एक दिन में अधिकतम 4 पीरियड की सीमा होने के कारण उनका पूरा मासिक वेतन इसी आधार पर तय होता था। इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कई बार कॉलेजों में व्याख्याताओं को जानबूझकर पीरियड कम दिए जाते थे, जिससे उनकी मासिक आय सीधे तौर पर प्रभावित होती थी। लंबे समय से अतिथि व्याख्याता संगठन एक निश्चित दैनिक वेतन की मांग कर रहे थे ताकि उन्हें आर्थिक अनिश्चितता से बचाया जा सके।

राम मंदिर चंदा मामले में ट्रस्ट भंग करने की मांग

मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री बोले-भगवान के नाम पर हुई लूट,प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए

रायपुर,11 जुलाई 2026। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता मामले को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रेस कांफ्रेंस कर रही है। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रायपुर के राजीव भवन में पीसी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया और चंदे में हुई कथित गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा और संघ के नेताओं ने भगवान राम के नाम पर लोगों की आस्था का दुरुपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 'इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा। राम को भाजपा का बताने की कोशिश की गई और राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय भी भाजपा ने अपने नाम कर लिया। '

'113 करोड़ रुपए खर्च हुए, कार्यक्रम राजनीतिक बन गया' : कांग्रेस ने दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए

गए,जबकि ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। पार्टी का आरोप है कि यह जनता का पैसा है और पूरे आयोजन को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल एक ही मूर्ति की स्थापना की गई और उस समय ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था।

'एसआईटी जांच के बाद कई सवाल खड़े हुए': कांग्रेस ने कहा कि एसआईटी जांच के बाद कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन लोगों पर पहले आरोप लगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें फिर से जिम्मेदारियां दे दी गईं। उन्होंने कहा कि जांच में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाओं में भी कई कमियां सामने आई हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं,इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

कांग्रेस ने उठाए तीन बड़े सवाल

- इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा?
- यदि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया?
- मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जा रही?

ट्रस्ट भंग करने की मांग

कांग्रेस ने मांग की कि वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 'भगवान श्रीराम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हो सकते। वे सबके हैं और कण-कण में विराजमान हैं। '

मंदिर की बावड़ी में डूबने से 2 बच्चों की मौत रायपुर में खेलते-खेलते गहरे पानी में गिरे ग्रामीण बोले-बावड़ी को चारों ओर से घेरा जाए

रायपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के कुंबरगढ़ स्थित प्राचीन चतुर्भुजी मंदिर परिसर की बावड़ी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। शनिवार सुबह दोनों बच्चे खेलते-खेलते बावड़ी के पास पहुंचे थे,तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरे पानी में गिर गए। घटना धरसींवां थाना क्षेत्र की है। टीआई राजेंद्र दीवान के मुताबिक, मृतकों की पहचान साक्षी साहू (07) और श्रवण धीवर (04) निवासी धरसींवां के कुर्रा गांव के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के

मुताबिक, शनिवार सुबह दोनों मंदिर परिसर के आसपास अन्य बच्चों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान वे प्राचीन बावड़ी के किनारे पहुंच गए और हादसे का शिकार हो गए। बच्चों के काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान दोनों बच्चों को बावड़ी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही धरसींवां पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए मॉर्चुरी भेज दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद ग्रामीणों का कहना है कि,मंदिर परिसर की यह प्राचीन बावड़ी काफी गहरी है।

कारोबारी ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप,पीएमओ पहुंची शिकायत तो मचा हड़कंप

बिलासपुर,11 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रियल स्टेट कारोबारी ने कोल्ड-ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर 37 साल की महिला से रेप किया है। उसका अश्लील वीडियो बनाकर करीब 8 महीने तक ब्लैकमेल भी किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत डाक के माध्यम से पीएमओ को भेजी। जिसके बाद स्वतः दर्ज की गई है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। पीड़िता का आरोप है कि, किसी को कुछ बताने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने,दुकान खाली कराने,जेल भिजवाने और झूठे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। आरोपी ने यह भी दावा किया कि, उसकी पहुंच बड़े पुलिस अधिकारियों तक है। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकारी के मुताबिक, मुंगेली नाका के पास किराए के कमरे में सिलाई सेंटर चलाने वाली महिला की पहचान भवन मालिक रियल स्टेट कारोबारी प्रशांत नारंग उर्फ बंटू नारंग (45) से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि सितंबर 2024 में

आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसका एक परिचित हाईकोर्ट का बड़ा वकील है, जो उसके पुराने केस में मदद कर सकता है। इसी बहाने उसने 8 सितंबर 2024 को दोपहर करीब दो बजे होटल ईस्ट पार्क बुलाया। पीड़िता का आरोप है कि होटल में आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक/पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। बेहोशी जैसी हालत में उसके साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना लिया। शिकायत के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया। डर और बदनामी की वजह से वह विरोध नहीं कर सकी। आरोपी अप्रैल 2025 तक अलग-अलग होटलों में बुलाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता का यह भी आरोप है कि, दिसंबर 2024 में आरोपी ने उसे दूसरी पत्नी की तरह रखने और शादी का भरोसा देकर अपने साथ बनाए रखा। जब भी महिला वीडियो डिलीट करने की बात करती, आरोपी टालमटोल करता रहा। बाद में उसने पीड़िता का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी फिलहाल मुंबई में है। पीड़िता का आरोप है कि,विरोध करने पर आरोपी ने मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो दिखाते हुए कहा कि, अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। दुकान खाली कराने,दोबारा जेल भिजवाने और झूठे मादक पदार्थ के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। डर और कथित रसूख के कारण पीड़िता सीधे थाने नहीं पहुंच सकी।

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर कांग्रेस का हमला,भूपेश बघेल बोले-सीनियर नेताओं को किनारे कर रही भाजपा

रायपुर,11 जुलाई 2026। भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटने पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, भाजपा बड़े नेताओं को दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकने का काम कर रही है, इसे यूज एंड थ्रो कहा जाता है। यही भाजपा की कार्यशैली है। नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ फ़ायर ब्रांड नेता पूर्व गृहमंत्री को किस तरह अपमानित कर रहे है। ये साफ-साफ नजर आ रहा है। भाजपा अब सीनियर नेताओं को किनारे करने की राजनीति कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब दौरे से रायपुर लौटे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने पंजाब दौरे को लेकर कहा, कांग्रेस की नई टीम घोषित हुई है। नियुक्ति के बाद

निश्चित रूप से कुछ बातें होती है। बहुत से साथी सोचते हैं पार्टी के लिए हमारी भी भागेदारी होनी चाहिए, चूंकि 2027 का चुनाव सभी के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में कोई भी कंप्रोमाइज्ड होगा वो नहीं चलेगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही खुद कंप्रोमाइज्ड हैं। इतिहास कवर्धा के वायरल वीडियो पर भूपेश बघेल ने कहा, कवर्धा का वीडियो सरकार की हकीकत को बता रहा है, क्योंकि सरकार को काम करने आता ही नहीं है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)